सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 244, नई दिल्ली

गुरुवार, 16 नवम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

मूर्ख व्यक्ति दूर-दूर तक खुशी तलाशता है, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है।

त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर उमडी यात्रियों की भीड़, एक-एक सीट के लिए मारा-मारी

संजय बाटला

दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद तक के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाईं गईं हैं। इसके बावजूद सारी तैयारियां फीकी नजर आईं।

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन चल रहा है। ऐसे में हर कोई अपने घर की ओर चल पड़ा है। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद तक के बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें चलाईं गईं हैं। इसके बावजूद सारी तैयारियां फीकी नजर आईं। ट्रेन में सीट के लिए यात्री मारा मारी करते नजर आए। जनरल डिब्बों में हालात बद से बदतर दिखे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

दिवाली के बाद छठ पर्व मनाने घर जाने वाले लोगों को भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही है। रेलवे ने छठ को लेकर विशेष प्रबंधन के तौर पर स्पेशल ट्रेन चलाई लेकिन भीड़ के सामने सारी तैयारी फीकी दिख रही हैं। त्योहार में शरीक होने के लिए जाने का उत्साह लोगों में इतना है कि वह किसी तरह ट्रेन में सफर करने के लिए तैयार है।

भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन संख्या 04650 अमृतसर से दरभंगा के लिए 16 नवंबर को चलाने का एलान किया है। इसी तरह ट्रेन संख्या 04640 श्रीमाता वैष्णो देवी से कटिहार के लिए 15 नवंबर को स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसके अलावा आनंद विहार टर्मिनल-पटना और नई दिल्ली-सहरसा जंक्शन के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन संख्या 02248 आनंद विहार टर्मिनल से पटना के लिए 16 और 18 नवंबर को देर रात 12:30 बजे चलेगी। एक अन्य ट्रेन 04016 नई दिल्ली से सहरसा के लिए 12, 15, 18 और 21 नवंबर को दोपहर 2:55 बजे चलेगी। मार्ग में यह ट्रेन मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़यि स्टेशन पर दोनों दिशाओं में ठहरेगी।

छठ पर गोरखपुर तक के लिए चलेगी स्पेशल सेवा

छठ पूजा के मौके पर नोएडा के सेक्टर-35 स्थित मोरना डिपो से गोरखपुर तक स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। बुधवार से 24 घंटे के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। परिवहन निगम की तरफ से सभी रूटों पर 20 नवंबर तक बसों के अतिरिक्त फेरे लगाने की घोषणा की गई है। छठ के अवसर पर मोरना डिपो से गोरखपुर तक स्पेशल बसें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेंगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर निगम बसों की संख्या बढ़ा देगा। डिपो के एआरएम एनपी सिंह ने बताया कि निगम की तरफ से अयोध्या व लखनऊ के रूट पर भी बसे चलाई जा रहीं हैं। दीपावली पर्व के मौके पर रोडवेज बसों से पिछले पांच दिनों में करीब दो लाख लोगों ने विभिन्न रूटों पर आवाजाही की है। नोएडा डिपो से 180 बसें मेरठ, आगरा, अलीगढ़, हरिद्वार, कासगंज, बदायूं और मथुरा सहित करीब बीस रूटों पर चलाईं जाती हैं।

advertisement Tariff
w.ef. 1st January 2023

परिवहन विशेष
दिल्ली, एनसीआर से प्रसारित लोकप्रिय साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र

in Rs. / Sq. Cm.

	Basic	3rd Page	Back Page	Front Page Semi Solus	Fornt Page Solus
Delhi Aur Delhi	BW - Colour	Colour	Colour	Colour	Colour
Delhi	100*	200*	250*	300	300

Special Instructions:-

- Innovation on any page will be accepted at a premium of 100% on applicable card rate.
- Any specified position will be accepted at a premium of 25% on applicable card rate.
- B/W advertisement on page 3/Back will charged at colour rate.
- Classified display advertisement will be charged on basic display rate.
- Pointers 4x4 sq. C. or 5x4 sq. cm. will be charged as per card rate.
- box reply charges (each box) will be charged Rs. 150/-
- Political advertisement - as applicable.

परिवहन विशेष में विज्ञापन के लिए ऑनलाईन भुगतान सीधे बैंक खाते/फ़ोन पे पर कर सकते हैं और विज्ञापन के मैटर के साथ ऑनलाईन भुगतान की रसीद व्हाट्सऐप नंबर 09212122095 या newstransportvishesh@gmail.com पर भेज सकते है। भुगतान करने के लिए *NEFT / IMPS / RTGS*
Account Name:-Transport Vishesh Limited
IFSC CODE :- INDB0001396
Cur Account no :- 259212122095
या Phone pay :- 9212122095

दिल्ली में लग सकता है ऑड-ईवन...? गोपाल राय बोले- प्रदूषण कम न होने पर कृत्रिम वर्षा पर करेंगे विचार

दिवाली की शाम के बाद से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा का गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। अब बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि आने वाले दो या तीन दिनों तक राजधानी में प्रदूषण की स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रहेगी। वहीं प्रदूषण कम न होने पर ऑड-ईवन पर विचार करेंगे।

नई दिल्ली। दिवाली की शाम के बाद से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा का गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। अब बुधवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि आने वाले दो या तीन दिनों तक राजधानी में प्रदूषण की स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रहेगी।

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में एक बार फिर हवा की गति में ठहराव के साथ-साथ तापमान में गिरता जा रहा है। ऐसे में दिवाली पर जो धुआं हुआ था वो अभी-भी आसमान में बना हुआ है। अभी अगले दो-तीन दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की ऐसी ही स्थिति दिखेगी और उसके बाद ही ऑड-ईवन या कृत्रिम बारिश कराने पर विचार किया जाएगा।

ऑड-ईवन पर करेंगे विचार: गोपाल राय

गोपाल राय ने कहा, 2-3 दिनों के बाद हवा की गति तेज हो सकती है। इसलिए उम्मीद है कि स्थिति बेहतर होगी। हम अभी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कल हम वैज्ञानिकों और विभागों के साथ बैठेंगे। अगर AQI 'गंभीर प्लस' श्रेणी में चला जाता है तो सरकार ऑड-ईवन जैसे सख्त उपायों के बारे में सोचेगी।

यमुना की सफाई का काम हुआ शुरू: पर्यावरण मंत्री

उन्होंने आगे कहा कि छठ पूजा के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तैयारियां की जा रही हैं, इस बार भी 1000 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कई टीमों ने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है।

दिल्लीवाले ध्यान दें! 2 हफ्ते तक इन सड़कों पर निकले तो होगी मुश्किल; देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। यह 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। आम लोगों को 19 नवंबर से 27 नवंबर तक मेले में प्रवेश दिया जाएगा। प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले में हर दिन 40000 लोगों के आने की संभावना है। ऐसे में प्रगति मैदान के आसपास कुछ रास्तों पर जाम की स्थिति हो सकती है।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में व्यापार मेला का उद्घाटन किया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर तक दो सप्ताह चलेगा।

19 नवंबर से आम लोगों की एंट्री

14 से 18 नवंबर तक केवल व्यापारिक आगंतुकों को मेले में प्रवेश की अनुमति होगी। आम लोगों को 19 नवंबर से 27 नवंबर तक मेले में प्रवेश दिया जाएगा। प्रगति मैदान में चल रहे व्यापार मेले (Delhi Trade Fair) में हर दिन 40,000 लोगों के आने की संभावना है। वीकेंड और छुट्टियों के दिन मेले में करीब एक लाख लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में प्रगति मैदान के आसपास कुछ रास्तों पर जाम की स्थिति हो सकती है।

इन सड़कों पर ट्रैफिक जाम की आशंका

ट्रैफिक एडवाइजरी (Delhi Traffic Advisory) के मुताबिक, मथुरा रोड, भैरों मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड और पुराना किला रोड पर ट्रैफिक जाम की आशंका है। ट्रैफिक पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले को देखते हुए व्यापार मेले में नहीं आने वाले लोगों से परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इन सड़कों से बचने का अनुरोध किया गया। साथ ही लोगों से प्रगति मैदान तक जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की सलाह दी गई है।

वाहनों को रुकने या पार्क करने की नहीं अनुमति

ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, मथुरा रोड और भैरों मार्ग पर किसी भी वाहन को कहीं भी रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि आगंतुकों के किसी भी वाहन को शेरशाह रोड, पुराना किला रोड, भगवान दास रोड और तिलक मार्ग पर पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया कि इन सड़कों पर पार्क किए गए वाहनों को हटा दिया जाएगा और अनुचित पार्किंग और कानूनी निर्देशों की अवज्ञा के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। खींचे गए वाहनों को नेशनल स्टेडियम की पार्किंग में गेट नंबर 5 पर पार्क किया जाएगा।

दिल्ली यातायात निर्देशिका

प्रगति मैदान में 14-27 नवंबर, 2023 तक होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के संबंध में

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2023 का आयोजन **14 से 27 नवंबर, 2023** तक प्रगति मैदान में किया जा रहा है। व्यापार मेले में प्रत्येक दिन लगभग 40,000 आगंतुकों के आने की संभावना है, सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान यह प्रति दिन लगभग 01 लाख होगा। मेले के दिनों में मथुरा रोड, भैरों मार्ग, रिंग रोड, शेरशाह रोड और पुराना किला रोड पर ट्रैफिक जाम की आशंका है। व्यापार मेले में न आने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए इन सड़कों से बचें।

समय

मेले में प्रवेश की अनुमति केवल **14 से 18 नवंबर, 2023** तक व्यावसायिक आगंतुकों को दी जाएगी। व्यापार मेला आम जनता के लिए **19 से 27 नवंबर, 2023** तक खुला रहेगा।

- गेट नंबर **5-ए, 5-बी, 7, 8 और 9** से आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा।
- **आगंतुकों** के लिए प्रवेश गेट नंबर **1, 4, 6 और 10** से होगा।
- प्रदर्शकों के लिए प्रवेश गेट नंबर **1, 4, 5 बी और 10** से होगा।
- **मीडिया कर्मियों** के लिए प्रवेश गेट नंबर **5-बी** से होगा।
- **आईटीपीओ अधिकारियों** के लिए प्रवेश गेट नंबर **9 और 1** से होगा।
- व्यापार मेले में सभी दिन शाम 05:30 बजे के बाद **कोई प्रवेश नहीं** होगा।
- **प्रगति मैदान में टिकटों की बिक्री नहीं होगी।** टिकट ऑनलाइन और चयनित मेट्रो स्टेशनों (सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर) पर बेचे जाएंगे।
- चालक चालित वाहनों, टैक्सियों और ऑटो के लिए ड्रॉपिंग पॉइंट आईटीपीओ के **गेट नंबर 3 और गेट नंबर 7** के सामने सर्विस लेन पर और बेसमेंट पार्किंग के प्रवेश द्वार के पास भी होगा।
- जन सुरक्षा के हित में मेले में प्रवेश पहले बंद किया जा सकता है।

#DPTrafficAdvisory

Delhi Traffic Police | @dtptraffic

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

छठ पर बिहार जा रही चलती बस बनी आग का गोला, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा के सेक्टर 96 के अंडरपास के पास एक बस में बुधवार को भीषण आग लग गई। इसमें 60 यात्री मौजूद थे। सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

नोएडा। जिले के सेक्टर 96 स्थित अंडरपास के पास एक बस में भीषण आग लग गई। हालांकि, इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बस में मौजूद सभी यात्री कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया।

पुलिस को घटना के बारे में 3 बजकर 15 मिनट पर मिली। हादसा नोएडा सेक्टर 96 नोएडा एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस में हुआ। जानकारी के मुताबिक बस में लगभग 60 यात्री सवार थे। बस सेक्टर 37 से चलकर बिहार के सिवान जा रही थी। इसमें छठ पर घर जाने के लिए कई यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि बस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है।

बिना डर के देर रात सफर कर सकेंगी महिलाएं, एयरपोर्ट से पूरे NCR में कैब चलाएंगे ट्रांसजेंडर व महिलाएं

दिल्ली एयरपोर्ट से देर रात महिलाएं-एनसीआर के किसी भी इलाके में जाने में संकोच नहीं करेंगी। पुरुष चालक की वजह से महिलाएं संकोच करती हैं। अब एयरपोर्ट से पूरे एनसीआर में महिलाएं और ट्रांसजेंडर कैब चलाती नजर आएंगी। शुरुआत 50 कैब से की जाएगी। धीरे-धीरे कैब की संख्या 300 तक की जाएगी। 50 कैब में से 40 कैब महिलाएं चलाएंगी जबकि 10 कैब ट्रांसपिपल (ट्रांसजेंडर) चलाएंगे।

जल्द ही एनसीआर की सड़कों पर ट्रांसपिपल कैब चलाते नजर आएंगे। कैब की सुविधा दिल्ली एयरपोर्ट से उपलब्ध होगी। शुरुआत 50 कैब से की जाएगी। धीरे-धीरे कैब की संख्या 300 तक की जाएगी। 50 कैब में से 40 कैब महिलाएं चलाएंगी, जबकि 10 कैब ट्रांसपिपल (ट्रांसजेंडर) चलाएंगे।

ट्रांसपिपल कैब चलाने के लिए उत्साहित

कुछ महीनों के बाद एनसीआर से बाहर भी यदि लोग जाना चाहेंगे तो कैब की सुविधा उपलब्ध होगी। कैब चलाने का मौका मिलने से ट्रांसपिपल काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि वह किसी से कम नहीं हैं। उनके ऊपर लोग विश्वास करके देखें। अपने व्यवहार व काम से वे लोग एनसीआर में कम से कम समय में विशेष पहचान बनाने को तैयार हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्टार्टअप कंसेप्ट से प्रभावित होकर वाईएमसीए फरीदाबाद से बीटेक कर रहीं रूमन एवं नार्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम से बीटेक कर रहे सूरज कुमार सिंह ने आर्बिन फियाकरे प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई है। यह ओला एवं उबर की तरह ही एप आधारित कैब सर्विस उपलब्ध कराएगी। अंतर यह होगा कि सभी चालक महिलाएं एवं ट्रांसपिपल होंगे।

इस सप्ताह से शुरू होगी कंपनी की सर्विस

यही नहीं सभी कैब कंपनी की होगी। इस सप्ताह से कंपनी की सर्विस शुरू हो जाएगी। सुरक्षा को ध्यान में रखकर सभी कैब जीपीएस से लैस होगी। यही नहीं कैब में एक पैनिक बटन होगा। गलत होने की आशंका पर बटन दबाते ही सूचना कंपनी के कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। कंपनी की सीईओ रूमन एवं सीओओ सूरज कुमार सिंह कहते हैं कि सर्विस शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ट्रांसपिपल को मुख्यधारा में लाना है।

महिलाएं तो अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं, लेकिन ट्रांसपिपल को अभी भी कोई नौकरी नहीं देता है। उन्हें अलग नजरिये से देखा जाता है। फिलहाल उनके पास 100 महिलाओं एवं ट्रांसपिपल की सूची उपलब्ध है जो नौकरी करने के लिए तैयार हैं। मांग के मुताबिक कैब की संख्या बढ़ाई जाएगी।

देर रात अकेले जाने से महिलाएं नहीं करेंगी संकोच

दिल्ली एयरपोर्ट से देर रात महिलाएं एनसीआर के किसी भी इलाके में जाने में संकोच नहीं करेंगी। पुरुष चालक की वजह से महिलाएं संकोच करती हैं। सूरज कुमार सिंह कहते हैं कि सभी कैब कंपनी की होगी। ऐसे में चालकों के ऊपर सौ फीसद कंपनी का नियंत्रण होगा।

जीपीएस की वजह से कैब कहां से कितने बजे चली और कितने बजे कहां तक पहुंची, पूरी जानकारी कंट्रोल रूम में अपडेट रहेगी। एप से बुकिंग की सुविधा तो रहेगी ही, एयरपोर्ट पर काउंटर से भी बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ट्रांसजेंडर चाहते हैं कि उन्हें लोग ट्रांसपिपल कहें। इसे ध्यान में रखकर कंपनी में ट्रांसजेंडर की जगह ट्रांसपिपल शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

अन्य कंपनियां भी ट्रांसपिपल को मौका दें

ट्रांसपिपल देवांश एवं कृष्णा का कहना है कि उनके भीतर प्रतिभा की कमी नहीं है। काफी संख्या में ट्रांसपिपल हर क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। उन्हें कंपनियां मौका दें। आर्बिन फियाकरे प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने उनलोगों को मौका दिया है। वे लोगों की सेवा करने के लिए बेहतर उत्साहित हैं। वे लोग इस तरह से काम करना चाहते हैं कि अन्य ट्रांसपिपल भी बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित हों।

आस्था निष्ठा का पर्व
छठ पूजा

- रूचि पाण्डेय

देश के कोने-कोने में बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो लोग जहाँ हैं वह अपने परिवार के साथ ही रहते है। इसी वजह से छठमनाने वालों की संख्या भी लगातर बढ़ती जा रही है, मुख्य रूप से बिहार में मनाए जाने वाले छठ पर्व का प्रभाव राज्य की सीमा लांघकर न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया है, जहाँ कहीं भी बिहार या पूर्वांचल के लोग प्रवास पर गये, वहीं भगवान भाष्कर के महापर्व छठ पूजा विधि-विधान से करने लग गये। छठ पर्व केवल आराधना ही नहीं, बल्कि यह बिहार की पारंपरिक सभ्यता-सांस्कृतिक के विरासत है। जिस सभ्यता व शालीनता से यह व्रत किया जाता है वह अपने में अतुलनीय है। 4 दिन तक चलने वाले छठ व्रत के दौरान व्रती भगवान भाष्कर और उनकी बहन छठि के लिए जिस भक्ति भाव से पूजा करती वह बड़ा कठिन है, वैसे तो छठ पूजा सूर्य देव के प्रति समर्पण है। यह पर्व सूर्य देव की बहन छठी की है, छठी की अंश सूर्य देव में ही है। सूर्य ने ही छठी का पहला व्रत किया था, तब से इस पर्व का नाम छठ पूजा के रूप में प्रचलित हुआ। उस समय से ही छठ पूजा की आराधना होने लगी। सूर्य की शक्ति की श्रोत है, उनकी पत्नी ऊषा और प्रत्युषा है, छठ में षष्ठी और सूर्य की पूजा के साथ इन दोनों देवियों की भी आराधना की जाती है। इन आराधनाओं के माध्यम से व्रती देव, देवियों की शक्तियों का गुणगान कर उनसे अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगती है। व्रती इस संसार के तमाम प्राणियों को रोग-दोष को दूर करने, मनुष्य के जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए आराधना करती है। गुजरते समय के साथ लोगों की आस्था छठपूजा में गहरी हो रही है इसका अन्दाजा तो छठ पर्व के मौके पर छठ घाट पर उमड़ने वाली भीड़ से लगाया जा सकता है, बदलते परिवेश में छठ पर्व में छठ पर्व मनाने के तौर-तरीके नहीं बदले है। आज पहनावा के तौर पर जीन्स, टॉप, सूट को ज्यादा तबोजो दिया जा रहा है, फिर भी व्रती महिलायें साड़ी व्रती पुरूष धोती पहनते है। सर (माथे) पर आँचल रखकर ही व्रती महिलाएं अर्ध्य अर्पण करती है। छठ में साफ-सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है चाहे घर हो या छठ घाट सब जगह की साफ-सफाई एक सप्ताह पूर्व से ही होने लगती है।

कठोर निर्जला और पवित्रता भरा छठा पर्व एक कठिन तपस्या है। जब अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है उस समय के दृश्य बड़ा ही लुभावना होता है मानों सारे कष्ट दूर हो गये, जो जहाँ होता है वहीं से उस समय छठी के आराधना आवश्यक करता है। अपने जीवन के लिए हर खुशियां मांगता है। संसार के नेत्र सूर्य देव ही है। कोई भी धर्म मानने वाला क्यों न हो सूर्य की पूजा अवश्य करते है, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के महापर्व छठ की छटा जिस तरह पैरा बैगनी रोशनी की तरह देश के अलावा विदेशों में फैला है, सभ्यता व सांस्कृतिक के चर्चा सुनकर बिहार के युवा अपने आप पर गर्व महसूस करते है। जब किसी राज्य में बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों का छठ पूजा के लिए विरोध होता है तो उस समय उन्हें बिहार के लोग आईना दिखाते है कि हमारे पास अमूल्य धरोहर, सभ्यता व शालीनता है जो किसी के पास नहीं है। छठ के इस पावन त्यौहार में लोगों की अस्था में बढ़ोतरी हो रही है जो धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां है।

गर्भ में पल रहे बच्चे के फेफड़े भी खराब कर सकती है जहरीली हवा ! प्रेग्नेंट महिलाएं तुरंत करें 5 काम, वरना...

एयर पॉल्यूशन कई जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है.एयर पॉल्यूशन कई जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है.

खराब एयर क्वालिटी प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है. जहरीली हवा की वजह से बच्चों को जन्म से ही अस्थमा समेत कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त हवा बेहद जहरीली है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है. इससे बचने की जरूरत है.

दिल्ली-एनसीआर में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो चुकी है. कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 और 600 के पार पहुंच गया है, जो बेहद गंभीर स्तर है. अगले कुछ सप्ताह तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत आसपास के शहरों की हवा जहरीली रहने की आशंका है. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इतना ज्यादा वायु प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है और आने वाले दिनों में अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है. जानकारों की मानें तो एयर पॉल्यूशन प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अत्यधिक घातक हो सकता है. ऐसे में गर्भवती महिलाओं को जहरीली हवा से खुद को हर हाल में बचाना होगा. आज एक्सपर्ट से जानेंगे कि खराब हवा कैसे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर रही है. साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दमघोंटू हवा से किस तरह बचाव किया जा सकता है.

नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित फोर्टिस ला फेम हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. त्रिपत चौधरी के मुताबिक एयर पॉल्यूशन प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बेहद खतरनाक होता है. प्रेग्नेंसी भ्रूण के विकास की अवधि होती है और इस दौरान वह पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होता है. प्रेग्नेंसी से लेकर जन्म के 2 वर्ष तक एयर पॉल्यूशन का असर बच्चे पर बुरी तरह पड़ता है. अगर प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाएं जहरीली हवा के संपर्क में आएंगी, तो गर्भ में बच रहे बच्चे के फेफड़ों की फंक्शनिंग में कमी हो सकती है और जन्म से ही सांस संबंधी बीमारी व अस्थमा की समस्या पैदा हो सकती है. वायु प्रदूषण की वजह से बच्चे का वजन कम हो सकता है और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है. एयर पॉल्यूशन भ्रूण के फेफड़ों के विकास को नुकसान पहुंचाता है. गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण में रहने से गर्भ में पल रहे बच्चों का ऑर्गन डेवलपमेंट बुरी तरह प्रभावित होता है और जन्म से ही कई परेशानियां हो सकती हैं. गर्भवती महिलाओं के श्वसन तंत्र को भी प्रदूषण से गंभीर नुकसान होता है.

प्रेग्नेंट महिलाएं किस तरह करें बचाव ?

डॉ. त्रिपत चौधरी कहती हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को इन दिनों सुबह-सुबह बाहर नहीं निकलना चाहिए. जब भी बाहर निकलें, तब N-95 मास्क का इस्तेमाल करें. गर्भावस्था में महिलाओं को अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखना चाहिए. पॉल्यूशन के दौरान स्मोकिंग करना बेहद खतरनाक हो सकता है और इससे फेफड़ों को पर डबल अटैक हो सकता है. ऐसे में स्मोकिंग से पूरी तरह दूरी बनाने में ही फायदा है. फेफड़ों को मजबूत रखने वाली एक्सरसाइज और योगासन करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर संभव हो तो घर के अंदर एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करें.

शिशुओं के लिए भी पॉल्यूशन खतरनाक

फोर्टिस ला फेम के नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अवधेश आहूजा के अनुसार जहरीली हवा नवजात शिशुओं की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाती है. नवजात

शिशु एक वयस्क की तुलना में 2-3 गुना तेज सांस लेते हैं. प्रदूषित हवा सीधे उनके फेफड़ों में जाकर इन्फेक्शन पैदा करती है. इन दिनों हॉस्पिटल में तमाम बच्चे खांसी, जुकाम, तेज सांस चलना, आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना और दमा जैसी की शिकायत लेकर आ रहे हैं. इन रोगों से ग्रस्त बच्चों की तादाद पॉल्यूशन बढ़ने के बाद काफ़ी बढ़ गई है. आने वाले दिनों में लोगों को बच्चों का विशेष खयाल रखना होगा.

छोटे बच्चों का ऐसे रखें खास खयाल

डॉ. अवधेश आहूजा कहते हैं कि जहरीली हवा से बचने के लिए शिशुओं और बच्चों को घर के अंदर ही ज़्यादा रखें. बाहर की हवा में खेलना दौड़ना कम करें, तो बेहतर होगा. नियमित टीकाकरण जरूर करवाएं. इससे कई जानलेवा बीमारियों से बचा जा सकता है. खांसी-जुकाम या सांस में परेशानी होने जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. घर में धूप, अगरबत्ती दूसरे कमरे में करें जहां शिशु ना हों. कालीन और पर्दों में जहां धूल जमी हो, तो उसका प्रयोग न करें. घर में अगर किसी को सर्दी या खांसी हो, तो नवजात शिशु से दूर रहें या हमेशा मास्क लगाकर रखें. केवल टीकाकरण के समय ही शिशु को घर से बाहर ले जाएं.

इंसानों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, 2050 तक बढ़ने वाली है मरने वालों की संख्या; एक रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने किया दावा

परिवहन विशेष न्यूज

द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के मध्य तक गर्मी से होनेवाली मौतों में 4.7 गुना की बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में फोसिल फ्यूल को तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें तत्काल एनर्जी ट्रांजिशन की जरूरत है ताकि ग्लोबल वॉर्मिंग को बढ़ने से रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2050 तक लाखों लोगों की मौत हो सकती है।

नई दिल्ली। इस सदी के मध्य तक यानी 2050 के आसपास वैश्विक स्तर पर गर्मी से होनेवाली मौतों में 4.7 गुना की बढ़ोतरी होने की आशंका है। द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की 8वीं वार्षिक रिपोर्ट में जहां एक ओर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तात्कालिक खतरों पर जोर दिया गया है। वहीं, इसमें सरकारों, कंपनियों और बैंकों से तेल और गैस में निवेश छोड़ने का आग्रह भी किया गया है।

साल 2023 की रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन को लेकर उदासीनता के नुकसान को उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि साल 2022 में, लोगों को 86 दिनों तक खतरनाक उच्च तापमान का सामना करना पड़ा। इसमें 60 प्रतिशत दिनों के लिए मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार था। रिपोर्ट के लेखक फोसिल फ्यूल में निवेश करने वाली संस्थाओं की 'लापरवाही' की भी आलोचना की है। इसमें कहा गया है कि लापरवाही के चलते बदलती जलवायु से अनुकूलन की लागत लगातार बढ़ी है।

रिपोर्ट में स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि हमें एनर्जी ट्रांजिशन की तत्काल आवश्यकता है। यानी हमें जलवायु को नुकसान न पहुंचाने वाली ईंधन चाहिए। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि तत्काल और बेहतर सवास्थ्य के लिए जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए गए प्रयास वैश्विक अर्थव्यवस्था को जीरो-कार्बन की ओर ले जा सकती है। यह बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करेगी।

तापमान 2.7 डिग्री तक बढ़ेगा

लैंसेट काउंटडाउन की कार्यकारी निदेशक डॉ. मरीना रोमानेलो ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकने के लिए मौजूदा प्रयास अपर्याप्त है। साल 2100 तक तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और 2022 में रिकॉर्ड उच्च ऊर्जा उत्सर्जन के साथ वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों का स्वास्थ्य अधर में लटक गया है।

वैश्विक कुपोषण का बढ़ा खतरा

रिपोर्ट कुल मिलाकर बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों का एक चिंताजनक चित्र प्रस्तुत करती है, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से चूक जाने पर सदी के मध्य तक गर्मी से संबंधित मौतों में 370% की वृद्धि होने का अनुमान है। तेजी से बढ़ती विनाशकारी चरम मौसमी घटनाओं ने जल सुरक्षा और खाद्य उत्पादन को खतरे में डाल दिया है, जिससे वैश्विक कुपोषण का खतरा बढ़ गया है।

कमजोर आबादी झेलेंगी समस्याएं

जलवायु परिवर्तन को कम करने में विफलता बढ़ते आर्थिक नुकसान में स्पष्ट है, जो साल 2022 में 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है और गर्मी के जोखिम के कारण संभावित श्रम घंटों में कमी की संभावना में 42% वृद्धि हुई है। डॉ. जॉर्जियाना गॉर्डन-स्ट्रैचन का कहना है कि इस संकट के ऊपर एक संकट है, जिसमें कमजोर आबादी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

रिपोर्ट में गंभीर समस्याओं के बावजूद एक उम्मीद की किरण भी मिलती है। लेखक वैश्विक उत्सर्जन में खतरनाक वृद्धि और फोसिल फ्यूल उद्योग में बढ़ते निवेश का हवाला देते हुए इससे तेजी से दूर जाने की वकालत करते हैं।

लाखों लोगों की बिना वजह हुई मौत

इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फोसिल फ्यूल के विस्तार से लाखों लोगों को बेवजह 'मौत की सजा' मिल गई। उन्होंने कहा कि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए तत्काल जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करना होगा।

गाली देने पर युवक की पिटाई गुप्तांग में दी रॉड,गंभीर

परिवहन विशेष। एसडी सेठी। विष्णु गार्डन के ख्याल इलाके में शराब के नशे में गाली गलौज देने की सजा पर चार युवकों ने पहले तो जमकर की पिटाई उसके बाद भी जब युवको का मन नहीं भरा तो उन्होंने अमानवीयता की सभी हदें पार करते हुए पीडित के सारे कपडे उतारे और जबरदस्ती उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड घुसेड दी।युवक को गंभीर हालत में पास के गुरू तेग बहादुर अस्पताल में ले जाया गया। जहां से उसे सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पीडित के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अशोक यादव को गिरफ्तर गिरफ्तार कर लिया है।जबकि फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीडित की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है।वह विष्णु गार्डन इलाके का निवासी है और फैक्ट्री में काम करता है।फिलहाल पुलिस बाकी तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दंबिश दे रही है।

व्यापार मेले में सैलानियों का लुभा रही मध्यप्रदेश की विरासत, पसंद आ रहे घरेलू सजावट के सामान

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सैलानी उत्पादों के जरिये मध्यप्रदेश की समृद्ध विरासत से सीधे जुड़ रहे हैं। लोगों को सिल्क और साड़ी के उत्पादों के साथ सौंधी मिट्टी से बने घरेलू सजावट के सामान खासे पसंद आ रहे हैं। महेश्वरी सिल्क की साड़ियां तीन हजार से लेकर पांच हजार तक की रेंज में उपलब्ध हैं। बटीक प्रिंट में लड़कियों के लिए सलवार-सूट के कपड़े हैं।

नई दिल्ली। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (International Trade Fair) की शुरुआत हो चुकी है। इसमें हर राज्य अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए उत्पाद लेकर आए हैं। चार नंबर हाल में मध्यप्रदेश का स्टाल लगाया गया है। यहां आ रहे सैलानी उत्पादों के जरिये मध्यप्रदेश की समृद्ध विरासत से सीधे जुड़ रहे हैं।

सजावट के सामान आ रहे पसंद

उन्हें यहां सिल्क और साड़ी के उत्पादों के साथ सौंधी मिट्टी से बने घरेलू सजावट के सामान खासे पसंद आ रहे हैं। मध्यप्रदेश के संत रविदास हस्तशिल्प व हतकरघा विकास निगम के केएस मिश्रा ने बताया कि महेश्वरी सिल्क और बटीक प्रिंट हमेशा सदाबहार रहा है। यह उत्पाद रानी अहिल्याबाई होल्कर के वक्त से तैयार किए जा रहे हैं।

साड़ी, सलवार सूट के भी कपड़े मिल रहे

आज भी उसी रूप में तैयार किए जाते हैं। गुणवत्ता में थोड़ा अंतर जरूर होता है, लेकिन कार्य पूरी तरह से हाथ से ही किया जाता है। इसलिए इन उत्पादों की मांग बनी रहती है। महेश्वरी सिल्क की साड़ियां तीन हजार से लेकर पांच हजार तक की रेंज में उपलब्ध हैं। बटीक प्रिंट में लड़कियों के लिए सलवार-सूट के कपड़े हैं। इनमें शिफान का दुपट्टा इस्तेमाल किया गया है। इनकी रेंज भी एक हजार ही रखी गई है।

टसर शिल्क के कुर्ते की मांग

शिफान के दुपट्टे से काफी आकर्षक बन गए हैं। भोपाल से आए राकेश शर्मा ने बताया कि टसर शिल्क के कुर्ते के कपड़े की भी खूब मांग है। यह 630 रुपये मीटर हैं। मध्यप्रदेश के स्टाल में करीब 15 स्टाल अलग-अलग उत्पादों के हैं। इनमें माटी कला बोर्ड का प्रतिनिधित्व छतरपुर से आईं पुष्पा कर रही हैं। उनके पास मिट्टी के स्टैंड, लटकाने वाले दिए, अगरबत्ती स्टैंड, संदूक सभी कुछ सजावटी सामान है।

स्टैंड की कीमत 150 रुपये है। अगरबत्ती स्टैंड 100 रुपये के हैं। पुष्पा ने बताया कि उनका पुश्तैनी काम है। लोगों को पसंद भी काफी आ रहे हैं। मध्यप्रदेश के स्टाल पर आईं, दिल्ली की रहने वाली सैलानी पायल ने बताया कि महेश्वरी और चंदेरी सिल्क की साड़ियां मिलना मुश्किल होता है। यहां अच्छी गुणवत्ता की साड़ियां मिल जाती हैं, वे हर साल यहां आती हैं। मेले की शुरुआत है, तो अभी और दिन वे आएंगी।

दुष्कर्म के आरोपी सरकारी कर्मचारी को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- भागने की आशंका निराधार है

दिल्ली की एक अदालत ने दुष्कर्म करने के आरोपी सरकारी कर्मचारी को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उसके भागने की आशंका निराधार है क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है। आरोपी 25 अक्टूबर से जेल में बंद है। अदालत ने कहा कि आरोपी को 30000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दी जाती है।

नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने दुष्कर्म करने के आरोपी सरकारी कर्मचारी को जमानत दे दी। दिल्ली की अदालत ने यह कहते हुए आरोपी को जमानत दी है कि उसके भागने की आशंका निराधार है क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है।

25 अक्टूबर से जेल में बंद है आरोपी

एडिशनल सेशन जज शमा गुप्ता सरकारी अधिकारी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी 25 अक्टूबर से जेल में बंद है। जज ने अपने हालिया आदेश में कहा कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय प्रासंगिक कारक यह हैं कि क्या कोई संभावना है कि जमानत पर रिहा होने के बाद, आरोपी फरार हो सकता है।

उसके छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है या क्या उसकी हिरासत में पूछताछ से आगे की जांच में मदद मिलेगी। आदेश में कहा गया कि वर्तमान मामले में आरोपी ने कथित घटना के बाद पुलिस को फोन किया था और उन्हें सूचित किया था कि महिला की हालत ठीक नहीं थी और उनके आने तक इंतजार किया गया था।

30 हजार के निजी मुचलके और जमानत राशि पर मिली बेल

इसके अलावा आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है। इसलिए च अधिकारी (आईओ) की यह बिना किसी आधार के आशंका है कि वह भाग जाएगा। अदालत ने कहा कि आरोपी के परिवार के सदस्यों द्वारा उसे धमकाने के संबंध में पीड़िता की दलील महज बेबुनियाद बयान थी जिसे किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा सत्यापित या प्रमाणित नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि आरोपी को 30,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने पर जमानत दी जाती है।

अब चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत करेगी आप, कल ही पीएम पर टिप्पणी को लेकर मिला था केजरीवाल को नोटिस

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

आप नेता राघव चड्ढा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को बीजेपी के एक्स हैंडल से सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किया गया। इसे चुनावी राज्य राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से भी पोस्ट किया गया।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक और भ्रामक कैंपेन चलाया है। पार्टी ने कहा कि वह चुनाव आयोग को इस संबंध में शिकायत दर्ज कराएंगे।

आप नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को एक मीटिंग को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें पार्टी के प्रतिनिधिमंडल अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। पार्टी की यह प्रतिक्रिया तब आई है, जब एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

चुनाव आयोग ने नोटिस में कहा था कि 'आप' के सोशल मीडिया हैंडल से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। आयोग ने आप से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर 16 नवंबर तक जवाब मांगा है।

बीजेपी की पोस्ट आचार संहिता का उल्लंघनः चड्ढा

चड्ढा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक कैंपेन चलाया है। 5 नवंबर को बीजेपी के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया। इसे चुनावी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल हैंडल से भी पोस्ट किया गया। यह आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है।

दिल्ली में घर खरीदने का शानदार मौका, DDA की सबसे बड़ी आवासीय योजना को एलजी से मंजूरी: 32 हजार से ज्यादा फ्लैट्स शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई डीडीए की बैठक में त्योहार विशेष आवासीय योजना को मंजूरी दी गई है। यह डीडीए की सबसे बड़ी आवासीय योजना है। इसमें पहली बार 11 सौ से अधिक लग्जरी फ्लैट भी शामिल किए गए हैं। द्वारका लोकनायकपुरम और नरेला सहित अन्य स्थानों पर अलग-अलग श्रेणियों के 32 हजार से अधिक नवनिर्मित फ्लैट बिक्री के लिए रखे गए हैं।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की अध्यक्षता में हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बैठक में त्योहार विशेष आवासीय योजना को मंजूरी दी गई। ई-नीलामी और पहले आओ-पहले पाओ (एफसीएफएस) दोनों आधार पर फ्लैट आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। पहले की आवासीय योजनाओं में शामिल होने के लिए दिल्ली में फ्लैट या भूखंड का मालिक न होने की शर्त रखी जाती थी।

DDA की सबसे बड़ी आवासीय योजना

इससे कई लोग फ्लैट लेने से वंचित रह जाते थे। इस योजना में इस तरह की कोई शर्त नहीं है। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि कि द्वारका, लोकनायकपुरम और नरेला सहित अन्य स्थानों पर अलग-अलग श्रेणियों के 32 हजार से अधिक नवनिर्मित फ्लैट बिक्री के लिए रखे गए हैं। यह डीडीए की सबसे बड़ी आवासीय योजना है। इसमें पहली बार 11 सौ से अधिक लग्जरी फ्लैट भी शामिल किए गए हैं। आवेदन से लेकर आवंटन और

कब्जे तक की पूरी प्रक्रिया डीडीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से होगी।

आवासीय योजना की विशेषता

द्वारका सेक्टर19बी में पेंटहाउस, सुपर एचआईजी और एचआईजी फ्लैट शामिल हैं। इसके सामने डीडीए का गोल्फ कोर्स होगा। सभी फ्लैट ई-नीलामी के माध्यम से मिलेंगे।

द्वारका सेक्टर 14 में 316 और लोकनायकपुरम में 647एमआइजी फ्लैट की भी ई-नीलामी होगी।

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलने वाले फ्लैट

द्वारका सेक्टर 19 बी-728 ईडब्ल्यूएस

द्वारका सेक्टर 14 – 316 एलआइजी और 1008 ईडब्ल्यूएस

लोकनायकपुरम-224 ईडब्ल्यूएस

नरेला- विभिन्न श्रेणियों के 28 हजार से अधिक फ्लैट। यहां अलग-अलग चरणों में फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

कोई भी व्यक्ति टोकन बुकिंग राशि का भुगतान करके तुरंत अपने पसंदीदा स्थान और मंजिल पर फ्लैट बुक कर सकता है।

फ्लैट की कीमत

फ्लैट की श्रेणी	न्यूनतम कीमत (रुपये में)
ईडब्ल्यूएस	11.5 लाख
एलआईजी	23 लाख
एमआईजी	01 करोड़
एचआईजी	1.4 करोड़
सुपर एचआईजी	2.5 करोड़
पेंट हाउस	5 करोड़

गाजियाबाद में इस रोड पर 2 दिन ट्रैफिक डायवर्ट, हिंडन पुल पर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध

गाजियाबाद में छठ पर्व पर जीटी रोड स्थित हिंडन नदी पुल के पास लगातार दो दिन यातायात डायवर्जन रहेगा। हिंडन नदी पुल पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया वाहनों को इस प्रतिबंध में छूट दी गई है। रविवार 19 नवंबर को दोपहर दो बजे से देर शाम तक जीटी रोड पर नया बस अडडा और मोहन नगर के बीच यातायात दोपहिया को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए बंद रहेगा।

गाजियाबाद। छठ पर्व पर जीटी रोड स्थित हिंडन नदी पुल के पास लगातार दो दिन यातायात डायवर्जन रहेगा। रविवार 19 नवंबर को दोपहर दो बजे से देर शाम तक जीटी रोड पर नया बस अडडा और मोहन नगर के बीच यातायात दोपहिया को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए बंद रहेगा उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए 20 नवंबर सोमवार को सुबह तीन बजे से डायवर्जन लागू हो जाएगा।

हिंडन पुलिस पर वाहनों के आवागमन पर बैन

एडीसीपी यातायात रामानंद कुशवाहा के मुताबिक छठ पर्व पर हिंडन नदी में महानगर में विभिन्न स्थानों पर लगातार दो दिन सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 19 नवंबर की शाम अस्तांचलगामी सूर्य को छठ व्रती अर्घ्य देंगी तथा 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है। सबसे बड़ा आयोजन जीटी रोड पर हिंडन पुल के पास होता है। इसलिए हिंडन नदी पुल पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया वाहनों को इस प्रतिबंध में छूट दी गई है।

यह रहेगा डायवर्जन

न्यू लिंक रोड, नया बस अडडा की ओर से हिंडन पुल की तरफ जाने वाले सभी वाहनों के लिए प्रतिबंध

मोहन नगर से हिंडन पुल की ओर सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा

कनावनी की ओर से हिंडन पुल की ओर सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा

नया बस अड्डा की ओर से निजी वाहन न्यू लिंक रोड से होते हुए एनएच-नौ के जरिए गंतव्य तक जा सकेंगे।

डायवर्जन का ये रहेगा समय

19 नवंबर को दोपहर दो बजे से रात करीब 8 बजे पूजा समाप्त होने तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। वहीं, 20 नवंबर को सुबह तीन बजे से दोपहर करीब 12 बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट है।

कुत्तों के आतंक से लोगों में खौफ, 24 घंटे में 8 बच्चों समेत 219 को बनाया शिकार

गाजियाबाद में 38 बच्चों समेत 219 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। सभी घायल अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी रेबीज का टीका लगवाने के लिए पहुंचे। 347 लोगों ने एआरवी की दूसरी व तीसरी डोज लगवाई है। घायलों में 28 महिलाएं और 24 बुजुर्ग भी शामिल थे। वहीं संजय नगर के संयुक्त अस्पताल में पांच साल की मोहिनी के घर से बाहर खेलते समय पालतू कुत्ते ने काट लिया।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में 38 बच्चों समेत 219 लोगों को कुत्तों ने काट लिया। सभी घायल अलग-अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी रेबीज का टीका लगवाने के लिए पहुंचे। 347 लोगों ने एआरवी की दूसरी व तीसरी डोज लगवाई है। घायलों में 28 महिलाएं और 24 बुजुर्ग भी शामिल थे।

जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डा. मनोज कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि भूड़भारत नगर के नौ साल के पृथ्वी, गौशाला फाटक के 13 वर्ष के सुरेंद्र, विजय नगर के 10 वर्षीय अनिल, बहरामपुर के 14 वर्षीय रोहन, तिगरी की आठ वर्षीय वैष्णवी को रात में मेला देखकर लौटते समय कुत्तों ने काट लिया। वहीं, संजय नगर के संयुक्त अस्पताल में पांच साल की मोहिनी के घर से बाहर खेलते समय पालतू कुत्ते ने काट लिया।

मंगलवार को लोगों ने लगवाई एआरवी

अस्पताल	नए केस	पुराने केस	
जिला MMG अस्पताल		86	76
संयुक्त अस्पताल	24	61	
सीएचसी डासना	16	56	
सीएचसी मुरादनगर	20	35	
सीएचसी मोदीनगर	18	38	
सीएचसी लोनी	21	29	
सीएचसी भोजपुर	18	25	
संयुक्त अस्पताल लोनी		16	27

कुत्ते को बचाने के चलते फिलसी बाइक

वहीं, दूसरी ओर एनएच-नौ पर मंगलवार शाम करीब छह बजे कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई जिससे बाइक सवार दंपति और उनका पांच वर्षीय पुत्र घायल हो गए। बाइक के पीछे चल रहा टेंपो सड़क पर गिरे बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में पलट गया। टेंपो में 12 लोग सवार थे। अधिकांश सवारी को मामूली चोट लगीं। एक घायल को अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद निवासी मुनेश गुरूग्राम की कंपनी में काम करते हैं। दीवाली पर वह परिवारक के साथ जहांगीराबाद गए थे। मंगलवार शाम मुनेश अपनी पत्नी पूनम और पांच वर्षीरय बेटे यश के साथ बाइक पर गुरूग्राम जा रहे थे। एनएच-नौ पर लाल कुआं से दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन पर हिंडन नदी पुल से पहले उनकी बाइक के आगे कुत्ता आ गया।

हरियाणा में बसों का चक्का जाम, भैया दूज पर बहनों की बढ़ी मुश्किलें; बस की आस में बस अड्डों पर लगी भीड़

हरियाणा के अंबाला में बस चालक की हत्या के विरोध को लेकर आज प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर हैं। भैया दूज के मौके पर हड़ताल की वजह से गुरुग्राम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों अपनी यात्रा के मुख्य बस स्टेंड पर सुबह से लोग बस का इंतजार में बैठे रहे।

गुरुग्राम। हरियाणा के अंबाला में बस चालक की हत्या के विरोध को लेकर आज प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर हैं। भैया दूज के मौके पर हड़ताल की वजह से गुरुग्राम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों अपनी यात्रा के मुख्य बस स्टेंड पर सुबह से लोग बस का इंतजार में बैठे रहे। वहीं, नूंह रोडवेज बस नहीं चलने से भैया दूज पर भाई के घर जाने वाली महिलाओं को परेशानी हो रही हैं। बता दें कि नूंह में 61 बसें चलती हैं, लेकिन हड़ताल होने की वजह से आज कोई भी बस नहीं चल रही है।

समझ नहीं आ रहा घर जाए तो सके...

बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही महिला ने बताया कि मुझे फरीदाबाद जाना है, लेकिन सुबह सात बजे से मैं बस का इंतजार कर रही हूं। पर कोई बस नहीं आ रही है।

वहीं, एक अन्य महिला ने बताया कि उन्हें आगरा जाना और वह सुबह आठ बजे से गुरुग्राम बस स्टैंड पर बस का इंतजार रही हैं, लेकिन कोई बस नहीं आ रही है। यात्रियों के अलावा बस स्टैंडों पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की भी भीड़ दिख रही है।

हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मोहन नगर इलाके में भी लोग बसों का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं।

एमएसपी खरीद व्यवस्था में सेंध लगाकर बिचौलिये

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

देश में 1966-67 में सबसे पहले गेहूं की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक अगस्त 1964 को एलके झा की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी घटित की थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में रबी सीजन की गेहूं, सरसों सहित छह प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। पिछले कुछ सालों से बुवाई के समय ही फसलों के एमएसपी की घोषणा करना अच्छी परंपरा मानी जा सकती है। इससे किसान भी कौन-सी फसल लेनी है इसका निर्णय आसानी से कर पाते हैं। एमएसपी की घोषणा करते समय यह भी दावा किया गया है कि इन सभी छह फसलों के एमएसपी का निर्धारण लागत से अधिक किया गया है जिससे किसानों के लिए यह फसलें लाभकारी सिद्ध हो सके। दावों की मानें तो लागत की तुलना में सर्वाधिक 102 प्रतिशत अधिक एमएसपी गेहूं की घोषित की गई है, सबसे कम कुसुम की लागत से 52 प्रतिशत अधिक है तो चना और जौ की लागत से 60 फीसदी अधिक घोषित की गई है। सरसों की लागत से 98 फीसदी तो मसूर की 89 प्रतिशत अधिक राशि तय की गई है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि लागत की तुलना में सभी छह फसलों की एमएसपी दरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

सरकार की मानें तो लागत में खाद-बीज, कीटनाशक, सिंचाई पर व्यय के साथ ही मानव श्रम का भी समावेश किया गया है। ऐसे में लागत से अधिक राशि मिलना किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है। पर यक्ष प्रश्न यही है कि फसल आने के बाद किसान को यह मूल्य मिलेगा ही इसकी क्या गारंटी है? सारा झगड़ा इसी को लेकर है कि एमएसपी घोषित होते ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि किसान को उसकी फसल का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य तो मिल ही जाए। यदि इस तरह की फूलप्रूफ व्यवस्था लागू हो जाए तो किसानों को सही मायने में एमएसपी व्यवस्था का फायदा मिल सकता है। दरअसल सब कुछ होने के बाद भी किसान आज भी ठगा महसूस करता है। यही कोई डेढ़ दो माह पुरानी बात होगी जग आम नागरिकों को टमाटर दो सौ रुपए से भी अधिक में खरीदना पड़ा आज वहीं टमाटर मण्डियों में दस रुपए के आसपास आ गया है। अब प्रश्न यह है कि टमाटर के दो सौ रुपए होने का लाभ आखिर ना तो उत्पादक किसान को मिला और ना ही आम नागरिकों को मिला। ऐसे में दोनों ही ठगे महसूस करते रह गए, सरकार की किरकिरी हुई वह अलग।

देश में 1966-67 में सबसे पहले गेहूं की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक अगस्त 1964 को एलके झा की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी घटित की थी। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था का एक विपरीत प्रभाव सामने आने पर कि किसान अन्य फसलों की जगह गेहूं की फसल पर ही केनद्रित होने लगे तो ऐसी स्थिति में सरकार ने अन्य प्रमुख फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने का निर्णय किया। केन्द्र सरकार द्वारा सीएसीपी यानी कि कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिश पर कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाने लगी। आज देश में 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसमें 7 गेहूं, धान आदि अनाज फसलें, 5 दलहनी, 7 तिलहनी, 4 नकदी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। नकदी फसलों में गन्ना की सरकारी खरीद मूल्य की सिफारिश गन्ना आयोग द्वारा की जाती है तो गन्ने की खरीद भी सीधे गन्ना मिलों द्वारा की जाती है। इसी तरह से कपास की खरीद सीसीआई यानी कि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा की जाती है। मुख्यतौर से अनाज की खरीद भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से और दलहन व तिलहन की खरीद नेफैड द्वारा राज्यों की सहकारी संस्थाओं और अन्य खरीद केन्द्रों के माध्यम से की जाती है। केरल सरकार ने 16 तरह की सब्जियों के बेस मूल्य तय कर सब्जी उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देने की पहल की है तो अब हरियाणा सरकार भी केरल की तरह हरियाणा में भी सब्जियों का बेस मूल्य तय कर कर रही है।

2004 में एमएस स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का एक फार्मूला सुझाते हुए सुझाव दिया कि उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी घोषित की जाए। एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में फसल के अनुसार प्रति हैक्टेयर लागत, खेती के दौरान अन्य खर्चों, भण्डारण की स्थिति, विदेशों में उपलब्धता आदि पैमाने पर आकलन कर प्रत्येक फसल की एमएसपी की सिफारिश की जाती है। 2004 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 2018-19 में उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुणा अधिक मूल्य घोषित करने का निर्णय किया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा एमआईएस यानी कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत एमएसपी के दायरे में नहीं आने वाली फसलों की खरीद की व्यवस्था करती आई है। राजस्थान में लहसुन की खरीद, प्याज की खरीद आदि इसका उदाहरण है। इस साल रबी फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही न्यूनतम 52 प्रतिशत से 102 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। रबी सीजन में सर्वाधिक असर गेहूं और सरसों पर पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए गेहूं की एमएसपी लागत की तुलना में 102 प्रतिशत और सरसों की लागत की तुलना में 98 प्रतिशत अधिक घोषित की गई है। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार गेहूं के 2275 रु., सरसों की 5650 रु., मसूर की 6425 रु., चना की 5440 रु., जौ की 1850 रु. और कुसुम की 5800 रु. प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।

यह तो साफ है कि गेहूं और धान की खरीद सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर की जाती रही है और इसका प्रमुख कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था के सुचारू संचालन और बाजार पर नियंत्रण रखना रहा है। अन्य फसलों का जहां तक सवाल है, देश के अधिकांश प्रदेशों में खाद्यान्नों की खरीद एफसीआई द्वारा राज्यों के मार्केटिंग फेडरेशनों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं द्वारा व तिलहनों और दलहनों की खरीद नैफड द्वारा भी इसी व्यवस्था के तहत की जाती रही है। किसी समय यह सामान्य धारणा व वास्तविकता थी कि बाजार में जब भी किसी फसल के भाव एमएसपी से नीचे आने लगते तो राज्यों के मार्केटिंग फैडरेशनों द्वारा खरीद की घोषणा करने मात्र से बाजार में भावों में हल्की तेजी तो तत्काल देखने को मिल जाती थी। इसी तरह से यह वास्तविकता भी थी कि एमएसपी पर खरीद शुरू करने के समय यह माना जाता था कि कुल उत्पादन का अधिकतम 25 से 30 प्रतिशत तक खरीद होते होते बाजार में उस फसल के भाव एमएसपी के बराबर या अधिक आ जाएंगे और वास्तविकता तो यह रही कि दस से 15 प्रतिशत तक खरीद होते होते मण्डियों में भाव लगभग एमएसपी के आसपास आ ही जाते थे। पर करीब एक दशक से स्थितियों में तेजी से बदलाव आया है। मानें या ना मानें पर यह काफी हद तक सही है कि एमएसपी खरीद व्यवस्था में अब निजी खरीददारों की भागीदारी बढ़ गई है। इस आरोप को सिरे से नकारा नहीं जा सकता कि छोटे किसानों से उनकी फसलों को कम दामों में खरीद कर उनके नाम से एमएसपी पर खरीद केन्द्रों पर बेच कर किसान के नाम पर उसका लाभ बिचौलिए लेने लगे हैं। यही कारण है कि इस तरह के उदाहरण आम हैं कि कई स्थानों पर उस क्षेत्र में कुल पैदावार से भी अधिक की खरीद एमएसपी पर देखने को मिल जाती है।

दरअसल बिचौलियों ने एमएसपी खरीद व्यवस्था में सेंध लगा दी है। किसान से ही खरीद और ऑनलाईन व्यवस्था के बावजूद इस व्यवस्था का लाभ बिचौलिए अधिक उठाने लगे हैं। सवाल यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारें एमएसपी व्यवस्था को फूलप्रूफ बनाना सुनिश्चित कर दें और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से मण्डियों में भाव नीचे जाते ही तत्काल खरीद आरंभ हो जाए तो निश्चित रूप से अन्नदाता को इस व्यवस्था का पूरा-पूरा लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही इस व्यवस्था में जिस तरह से सेंध लगाई गई है, उसे रोकने के भी ठोस प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बाजार व्यवस्था का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि जब तक किसान की पूरी फसल बाहर नहीं आ जाती तब तक क्या कारण है कि बाजार में उस फसल के भाव एमएसपी के बराबर नहीं आते। इसका पर्दे के पीछे का खेल यही लगता है कि बिचौलियों ने इसका तोड़ निकाल लिया है और वह यह कि किसान से उसकी फसल और डिटेल ले लेते हैं और फिर किसान के नाम से लाभ यह ताकतें ले जाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्षेत्र में उत्पादित फसल से अधिक खरीद के आंकड़े मिलना आम होता जा रहा है। ऐसे हालात में सरकार का और अधिक दायित्व हो जाता है ताकि व्यवस्था को प्रभावित करती ताकतों को बाजार से हटाया जाये।

Royal Enfield Classic 350 को टक्कर देने आ गई Honda की धांसू बाइक, कंपनी ने जारी किया टीजर

कंपनी सीबी के लिए हैशटैग का इस्तेमाल कर रही है जिसका मतलब मौजूदा Hness CB350 के सामान्य है। Hness CB350 एक नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल है जिसे होंडा द्वारा सेल किया जा जा रहा है। नई मोटरसाइकिल होंडा की लाइनअप में सबसे सस्ती 350 सीसी मोटरसाइकिल हो सकती है। ये कुल चार वेरिएंट्स DLX DLX Pro Chrome और लिगेसी एडिशन में आएगी।

नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने एक नई मोटरसाइकिल का टीजर जारी किया है, जिसे वाहन निर्माता कंपनी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च करेगी। कंपनी सीबी के लिए हैशटैग का इस्तेमाल कर रही है जिसका मतलब मौजूदा H'ness CB350 के सामान्य है। नई मोटरसाइकिल केवल होंडा के बिगबिंग आउटलेट्स के माध्यम से बेची जाएगी।

Honda H'ness CB350

इस टीजर फोटो में एक मोटरसाइकिल को सप्लिट सीट सेटअप, एक ग्रैब रेल और स्विचगियर के साथ दिख रही है। जो जो H'ness पर है। इसके अलावा, टीज़र में निसिन कैलिपर के साथ फ्रंट डिस्क ब्रेक भी दिख रहा है और शॉक एब्जॉर्बर अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की तरह कवर किया गया है। H'ness CB350 और CB350RS के साथ प्लेटफार्म और इंजन साझा करेगी जो पहले से ही मार्केट में ब्रिकी के लिए उपलब्ध है।

Honda H'ness CB350 इंजन

H'ness CB350 एक नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल है जिसे होंडा द्वारा सेल किया जा जा रहा है। इसमें एक्सेसरीज किट का इस्तेमाल करके अनुकूलित किया जा सकता है। CB350 RS एक स्क्रैम्बलर है। क्योंकि नई मोटरसाइकिल H'ness और CB350RS के समान प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, इंजन साझा किया जाएगा। यह 350 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा जो 5,500 आरपीएम पर 21 बीएचपी और 3,000 आरपीएम पर 30 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट जनरेट करता है। ये 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है।

Honda H'ness CB350 कीमत

नई मोटरसाइकिल होंडा की लाइनअप में सबसे सस्ती 350 सीसी मोटरसाइकिल हो सकती है। ये कुल चार वेरिएंट्स DLX, DLX Pro, Chrome और लिगेसी एडिशन में आएगी। इस मोटरसाइकिल की कीमत 2.10 लाख से शुरू होती हैं और 2.16 लाख रुपये तक जाती है। CB350RS दो वेरिएंट DLX और न्यू ह्यू एडिशन में आती है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 2.15 लाख रुपये से लेकर 2.19 लाख रुपये तक जाती है।

2024 KTM 990 Duke से उठा पर्दा, जबरदस्त इंजन के साथ इन फीचर्स से लैस है ये लीटर क्लास बाइक

KTM ने EICMA 2023 में All New 990 Duke को पेश कर दिया है। इसका मुकाबला अन्य लीटर-क्लास नेकेड मोटरसाइकिलों से होगा। 2024 KTM 990 Duke को पावर देने वाला एक नया LC8c इंजन है जो यूरो 5+ के अनुरूप है। ये 947 सीसी पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन है। KTM 990 Duke को पूरी तरह से नए स्टील ट्यूब फ्रेम के आसपास विकसित किया गया है।

नई दिल्ली। KTM ने EICMA 2023 में All New 990 Duke को पेश कर दिया है। इसका मुकाबला अन्य लीटर-क्लास नेकेड मोटरसाइकिलों से होगा। नई मोटरसाइकिल लाइनअप में 890 DUKE GP से ऊपर होगी। 990 ड्यूक का उत्पादन ऑस्ट्रिया के मैटीघोफेन में केटीएम के मेन प्लांट में किया जाएगा। फिलहाल, KTM की 990 Duke को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की कोई योजना नहीं है। आइए, इसकी सभी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं।

इंजन

2024 KTM 990 Duke को पावर देने वाला एक नया LC8c इंजन है, जो यूरो 5+ के अनुरूप है। ये 947 सीसी, पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन है। यह पावरट्रेन 9,500 आरपीएम पर 121 बीएचपी की अधिकतम पावर और 6,750 आरपीएम पर 103 एनएम का पीक टॉर्क आउटपुट देता है।

इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है और राइडर क्विकशिफ्टर का विकल्प भी चुन सकता है।

स्पेसिफिकेशन

KTM 990 Duke को पूरी तरह से नए स्टील ट्यूब फ्रेम के आसपास विकसित किया गया है। सबफ्रेम एक एल्यूमीनियम डाइकास्ट भाग है, जिसमें सीट के नीचे एक एकीकृत एयरबॉक्स और एयर इंटेक होता है। इसके अलावा, स्विंगआर्म भी नया है और ट्रिपल क्लैंप जाली एल्यूमीनियम से बना है। 990 ड्यूक के पहिए 17 इंच के हैं और 1290 सुपर ड्यूक आर से लिए गए हैं, लेकिन दो तरफा स्विंगआर्म को शामिल करने के लिए थोड़ा अपडेट किया गया है। इन्हें मानक के रूप में ब्रिजस्टोन S22 टायर दिए गए हैं।

डायमेंशन

फ्रेम को सामने की ओर 43 मिमी WP एपेक्स ओपन कार्ट्रिज फोर्क्स द्वारा सस्पेंड किया गया है, जिसमें 140 मिमी का ट्रैवल है। ये कम्प्रेशन और रिबाउंड एडजस्टेबल के साथ आता है जिसे फोर्क्स के शीर्ष पर मौजूद क्लिकर्स के माध्यम से किया जा सकता है। पीछे की तरफ, एक WP एपेक्स मोनोशॉक है, जिसे रिबाउंड के लिए 5-क्लिक सेटिंग और मैन्युअल प्रीलोड एडजस्टमेंट के माध्यम से एडजस्ट किया जा सकता है।

टाटा अल्ट्रोज को खरीदने का शानदार मौका, कंपनी दे रही है बंपर छूट

वाहन निर्माता कंपनी अपनी कार टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर 35 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस कार की एक्स शोरुम कीमत 6.60 लाख रुपये है। इसके अलावा 5 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। ये नवंबर 2023 महीने के अंत तक वैलिड है। Tata Altroz को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिली है।

दिल्ली। भारतीय बाजार में टाटा की कारें सेफ्टी के लिए जानी जाती है। टाटा मार्केट में सबसे अधिक गाड़ियों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। अगर आप इस महीने टाटा की एक नई कार खरीदने की प्लैनिग कर रहे हैं तो आपको बता दें, ये एक सुनहरा मौका है। क्योंकि वाहन निर्माता कंपनी अपनी कार टाटा अल्ट्रोज (Tata Altroz) पर 35 हजार रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। इस कार की एक्स शोरुम कीमत 6.60 लाख रुपये है। मार्केट में टाटा अल्ट्रोज की बात करें तो बलेनो और ग्लैंजा को टक्कर देने वाली प्रीमियम हैचबैक कार पर 20 हजार रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 10 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। इसके अलावा 5 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। ये नवंबर 2023 महीने के अंत तक वैलिड है।

Tata Altroz सेफ्टी रेटिंग

Tata Altroz को सेफ्टी के मामले में 5 स्टार रेटिंग मिली है। सेफ्टी के लिए इस कार में कई दमदार फीचर्स मिलते हैं। इस कार में रियर पार्किंग सेंसर, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, डुअल एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वे कंट्रोल मिलता है।

Tata Altroz इंजन

इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल -सीएनजी और 1.5 लीटर डीजल का ऑप्शन मिलता है। इसके इंजन को 5 स्पीड यूनिट के साथ जोड़ा गया है। इसे 6 स्पीड का डीसीए ट्रांसमिशन केवल 1.2 लीटर एनए पेट्रोल तक सीमित है। इसके इंजन को RDE और BS6 फेज-2 एमिशन नॉर्म्स में अपडेट किया गया है।

ठंड ने दे दी दस्तक तो विंडशील्ड के ऊपर जमने वाली फॉग से ऐसे पाएं निजात, अपनाएं ये टिप्स

Car Driving Tips धुंध के समय ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को सड़क पर कम दिखाई देता है। कार विंडशील्ड के ऊपर जमने वाली फॉग का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है तापमान जो ठंड के मौसम में काफी कम हो जाता है। कार की विंडशील्ड पर जमी फॉग को हटाने के लिए अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते हैं तो कार की खिड़कियों को खोल सकते हैं।

नई दिल्ली। ठंड ने अब दस्तक दे दी है। इस मौसम में कार चलाने में काफी दिक्कत होती है। जिसके कारण सड़क हादसा भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धुंध के समय ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को सड़क पर कम दिखाई देता है। इसके साथ ही कार के विंडशील्ड पर जमा भाप भी इसका कारण बन जाती है। आज हम आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जिसे अपनाकर आप आराम से इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं।

क्यों जमती है फॉग

कार विंडशील्ड के ऊपर जमने वाली फॉग का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है तापमान जो ठंड के मौसम में काफी कम हो जाता है। कार के बाहर के तापमान कम होने और अंदर के तापमान के अधिक होने के कारण जब ठंडी हवा विंडशील्ड से टकराती है तो वो भाप बन जाती है जिसके कारण कार विंडशील्ड के ऊपर जमने वाली फॉग का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है। जिसके कारण हादसे भी हो जाते हैं।

कार में हटीर चलाएं

अगर कार के विंडस्क्रीन पर भाप जम जाती है तो कार के हीटर को चालू कर सकते हैं। इससे कार के अंदर मौजूद की नमी खत्म हो जाती है। इसके कारण भाप कम जमेगी।

ठंड में एसी चलाएं

कार में एसी सर्दी और गर्मी दोनों में काम आता है। कई बार विंडशील्ड पर फॉग जमने की स्थिति में कार के एसी को चलाकर अंदर और बाहर के तापमान को एक जैसा करना पड़ता है। जिससे विंडशील्ड पर जमने वाले फॉग को कम किया जा सकता है।

कार की खिड़कियां खोलें

कार की विंडशील्ड पर जमी फॉग को हटाने के लिए अगर आप एसी नहीं चलाना चाहते हैं तो कार की खिड़कियों को खोल सकते हैं। जिसके कारण आप फॉग जमा होने वाली समस्या से निजात पा सकते हैं। ड्राइविंग के दौरान अगर आपकी कार के विंडशील्ड पर फॉग जमती है तो आप अपनी कार की चारों खिड़कियों को खोल सकते हैं।

भारतीय विश्वविद्यालयों का कटु सत्य

डा. वरिंदर भाटिया

देसी विश्वविद्यालयों को लेकर ताजा खबर है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित एक रैंकिंग के अनुसार भारत अब 148 विश्वविद्यालयों के साथ एशिया में 'सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली' बन गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 अधिक है। इसके बाद 133वें स्थान के साथ चीन और 96वें स्थान के साथ जापान का स्थान है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बजट का 65 फीसदी हिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों को मिलता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35 फीसदी ही प्राप्त होता है। वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। इसकी बजाय विदेशी विश्वविद्यालयों में कॉलेज फैकल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके सहकर्मियों और विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में विद्यार्थियों और सहकर्मियों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर प्रोफेसरों के प्रदर्शन के ऑडिट की एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर दूसरे इनपुट्स जैसे रिसर्च पेपर, शिक्षकों के पब्लिकेशंस को भी प्रदर्शन ऑडिट में जोड़ा जाना चाहिए'

देसी विश्वविद्यालयों को लेकर ताजा खबर है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित एक रैंकिंग के अनुसार भारत अब 148 विश्वविद्यालयों के साथ एशिया में 'सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली' बन गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 अधिक है। इसके बाद 133वें स्थान के साथ चीन और 96वें स्थान के साथ जापान का स्थान है। म्यांमार, कंबोडिया और नेपाल भी पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं। क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा 2024 विश्वविश्वविद्यालय रैंकिंग एशिया को जारी कर दिया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-एशिया में भारत में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और रैंकिंग विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में एशिया के कुल 856 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। लेकिन सिर्फ 250 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग को ही विभिन्न मानकों की कसौटी पर परखा गया है, बाकियों को एक झुंड की शक्ल में रखा गया है। क्यूएस की वेबसाइट पर पड़ताल की गई तो कई तथ्य देखने को मिले। कटु हकीकत तो यह है कि एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में पहले 10 में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। पहले स्थान पर चीन की पेंकिंग यूनिवर्सिटी, 2. रैंकिंग पर हांगकांग यूनिवर्सिटी, 3. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, 4. नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, 5.त्सिंघुआ विश्वविद्यालय बीजिंग, 6. ज्हेझियंग यूनिवर्सिटी हांगझाऊ, 7.फुदान यूनिवर्सिटी शंघाई, 8. योंसेई यूनिवर्सिटी सेओल (दक्षिण कोरिया), 9. कोरिया यूनिवर्सिटी सेओल व 10. चायनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग हैं।

इसमें 4 विश्वविद्यालय चीन में हैं, जबकि हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के 2-2 और सिंगापुर के एक विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। भारत का एक भी शैक्षिणिक संस्थान इस रैंकिंग में पहले 39 स्थान पर नहीं है। 40वें स्थान पर आईआईटी मुंबई को रखा गया है। लेकिन हमारे अखबार इसे पहले स्थान पर बता रहे हैं। असल में क्यूएस रैंकिंग ने दक्षिण एशिया की अलग से रैंकिंग जारी की है जिसमें आईआईटी मुंबई को पहला मुकाम हासिल है। आईआईटी मुंबई की वर्ल्ड रैंकिंग 149 है। इसलिए यह कहना कि हम एशिया में अव्वल स्थान पर पहुंच चुके हैं, ठीक नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो भारत का मध्य वर्ग अपने बच्चों को ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह प्रवेश दिलाने की जुगत में न लगा होता। देश के विश्वविद्यालय अनेक मुश्किलों से दो-चार हैं। अपर्याप्त संसाधन और सुविधाओं के अतिरिक्त छात्रों को सलाह देने के लिए सीमित संख्या में गुणवत्तापूर्ण संकाय ही उपलब्ध हैं। अधिकांश शोधार्थी फेलोशिप के बिना शोधरत्त हैं या उन्हें समय पर फेलोशिप प्राप्त नहीं हो रही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके शोधकार्य को प्रभावित करता है। इसके अलावा यूजीसी की लघु और वृहद अनुसंधान परियोजना योजनाओं के तहत प्रदत्त अनुदान वित्त वर्ष 2016-17 में 42.7 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में मात्र 38 लाख रुपए रह गया है। भारत में 1040 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, लेकिन 2.7 फीसदी में ही पीएचडी कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है क्योंकि वे वित्तपोषण की कमी और खराब अवसंरचना से ग्रस्त हैं। काफी जगह शैक्षणिक मानकों और प्रक्रियाओं को बहाल नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा विश्वविद्यालयों की वित्तीय समस्या की गंभीरता को समझना होगा। अनेक विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे में निवेश घटा है। केंद्रीय स्तर पर वित्त वर्ष 2022-23 में छात्र वित्तीय सहायता को घटाकर 2078 करोड़ रुपए कर दिया गया (वित्त वर्ष 2021-22 में 2482 करोड़ रुपए)। अनुसंधान और नवाचार हेतु आवंटन में 8 फीसदी की कमी आई जो वर्तमान में 218 करोड़ रुपए रह गया है। उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी जो संस्थानों को सभी अवसंरचना ऋणों के लिए धन मुहैया कराती है, के बजट को वित्त वर्ष 2020-21 में 2000 करोड़ रुपए से घटाकर वित्त वर्ष 2021-22 में एक करोड़ रुपए कर दिया गया। कुछ सीमित विकल्पों के साथ विश्वविद्यालयों को ऋण लेने के लिए विवश किया गया है। इसमाई सुधार जरूरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वित्त वर्ष 2021-22 में 4693 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 4900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन नकदी प्रवाह में कमी के कारण डीम्ड/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वेतन भुगतान में देरी हुई। संकाय सदस्यों को वेतन प्राप्त होने में महीनों तक देरी का सामना करना पड़ता है। अधिकांश विश्वविद्यालय घाटे में चल रहे हैं। मद्रास विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए से अधिक का संचित घाटा झेलना पड़ा, जिससे उसे राज्य सरकार से 88 करोड़ रुपए का अनुदान लेने हेतु विवश होना पड़ा। अन्य राज्यों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उच्च शिक्षा में अधिकतर भर्तियां राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों द्वारा की जाती हैं। लेकिन तुलनात्मक रूप से इन राज्य विश्वविद्यालयों को कम अनुदान मिलते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बजट का 65 फीसदी हिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों को मिलता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35 फीसदी ही प्राप्त होता है। वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जिम्मेदारी और प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। इसकी बजाय विदेशी विश्वविद्यालयों में कॉलेज फैकल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके सहकर्मियों और विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में विद्यार्थियों और सहकर्मियों द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर प्रोफेसरों के प्रदर्शन के ऑडिट की एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर दूसरे इनपुट्स जैसे रिसर्च पेपर, शिक्षकों के पब्लिकेशंस को भी प्रदर्शन ऑडिट में जोड़ा जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षण के पेशे को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए फैकल्टी को कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना चाहिए। विश्वविद्यालयों को ऋण और वित्तीय सहायता के लिए समर्पित वित्तपोषण धारा स्थापित करने के साथ-साथ वित्तपोषण में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है। स्टार्टअप रॉयल्टी और विज्ञापन जैसे अन्य राजस्व धाराओं का उपयोग करने के लिए भी विश्वविद्यालयों को छूट दी जानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की सख्त जरूरत है।

संपादक की कलम से

चुनावी हवा का रुख

प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि वह 'हवा का रुख' पढऩे में सक्षम हैं। यह दावा छत्तीसगढ़ चुनाव के संदर्भ में किया गया। प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार की 'चला-चली' की बेला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चुनाव हार रहे हैं। दरअसल यह चुनावी मौसम का दौर है। कांग्रेस नेता भी दावे कर रहे हैं कि भाजपा की करारी पराजय होगी। कांग्रेस पांचों राज्यों में विजयी होने के भी दावे कर रही है। बेशक प्रधानमंत्री को 'हवा के रुख' की जानकारी रहती है, क्योंकि सभी स्तरों पर खुफिया एजेंसियां उन्हें ब्रीफ करती हैं। जो खुफिया लीड्स प्रधानमंत्री तक पहुंचती हैं, उनमें चुनावी आकलन भी शामिल होते हैं, लेकिन खुफिया विश्लेषण चुनाव के संदर्भ में गलत भी होते रहे हैं। बेशक प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव है, लेकिन कई राज्यों में वह 'हवा का रुख' पढऩे में नाकाम साबित हुए हैं। भाजपा कर्नाटक, हिमाचल, पंजाब आदि राज्यों के विधानसभा चुनाव हार गई, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पार्टी के स्टार प्रचारक थे। उन्होंने खूब जनसभाओं को संबोधित किया। उनके 'रोड शो' भी आयोजित किए गए और उन्हें जनता का जबरदस्त समर्थन मिलता भी दिखाई दिया, लेकिन भाजपा पराजित हो गई।

भाजपा पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में सत्तारूढ़ है और हिमाचल में भी उसकी सत्ता हर पांच साल बाद आती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा आज तक पंजाब की राजनीतिक और चुनावी 'हवाओं का रुख' नहीं जान पाए हैं, ताकि वे चुनावी प्रतिद्वंद्विता में शामिल रह सकें। अकाली दल के साथ गठजोड़ कर चुनाव लडऩे की बात और है, लेकिन पंजाब में अकेली भाजपा लगभग 'शून्य' है। तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश आदि दक्षिणी राज्यों में भाजपा आज भी लगभग गायब है, जबकि वह केंद्र सरकार में साढ़े नौ साल शासन कर चुकी है और आम चुनाव तक 10 साल पूरे कर लेगी। 2024 के आम चुनाव के जनादेश के प्रति भी भाजपा और प्रधानमंत्री आशान्वित हैं। देश के कई राज्यों में नरेंद्र मोदी पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव रह चुके हैं। वहां आरएसएस की शाखाएं भी हैं। वह समर्थन भी भाजपा के साथ है और उन राज्यों में हिंदू वोट बैंक भी व्यापक और सुदृढ़ है, लेकिन वहां के हिंदू, ओबीसी और दलित आदि भाजपा के पक्ष में, चुनावी तौर पर, ध्रुवीकृत नहीं होते। उन राज्यों की 'हवाओं का रुख' प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं पढ़ पाते? तेलंगाना में भाजपा खूब सक्रिय थी और सत्ता के लिए भरपूर कोशिशें कर रही थी, लेकिन संगठन में अचानक कुछ हुआ अथवा 'हवा का रुख' बेहद विपरीत लगा, लिहाजा कोशिशें शिथिल पड़ गईं। अब 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी को, किस राज्य में कितना, जनादेश हासिल हुआ? वैसे राजस्थान और मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकारें बनने के आसार हैं और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ही सरकार बरकरार रह सकती है।

अभी तक जितने भी सर्वेक्षण किए गए हैं और जो भी उनके निष्कर्ष रहे हैं, उनमें भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हिस्से में ही है। इसका बुनियादी कारण यह है कि विपक्ष में होने के बावजूद भाजपा पूरे पांच साल निष्क्रिय दिखाई दी है। डॉ. रमन सिंह लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विपक्ष में आते ही उन्हें भी हाशिए पर धकेल दिया गया। हालांकि वह अब भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा पूरे पांच साल कांग्रेसी सरकार के लिए चुनौती नहीं बन सकी। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभाओं में 'हवा के रुख' के दावे किए हैं और कांग्रेसी मुख्यमंत्री बघेल के पराजित होने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि 'महादेव सट्टा एप' और 508 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री को दी गई घूस के गंभीर आरोप हवाओं में हैं। असली स्थिति जल्द स्पष्ट होगी।

राय

हिमाचली पादुका को इंतजार

हिमाचल के लापचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन व सैनिक शिविर में दिवाली का उत्साह सांझा करना, देश के प्रति कत्र्तव्य की एक सुनहरी याद है। सीमांत क्षेत्रों में असामान्य परिस्थितियों में तैनात सैन्य कर्मियों से रूबरू होने की परंपरा में, प्रधानमंत्री का दौरा राष्ट्रीय घटनाक्रम है, लेकिन कमोबेश ऐसी ही परिस्थितियों में हिमाचल के भी कई गांव और काम अपने हिस्से की दुरुहता बटोरते हैं। ऐसे में भले ही प्रधानमंत्री का यह दौरा संवेदनशील व सामरिक महत्त्व की प्रतीक्षा को आश्वस्त और सुरक्षा की समीक्षा करता हो, लेकिन प्रदेश हर रास्ते पर अपनी पादुकाएं बिछाए न जाने कब से उनका इंतजार कर रहा है। जब से हिमाचल में डबल इंजन सरकार नहीं रही, पर्वतीय प्रदेश के लिए पीएमओ का व्यवहार और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सरोकार बदल गया है। लापचा कई मायनों में राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यहां पारिस्थितिकीय स्थिति हिमाचल की विडंबनाओं को भी दर्शाती है। बेशक सीमांत क्षेत्रों के गांवों तक भारत सरकार रोड नेटवर्क को सशक्त कर रही है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों से निकलती मौसमी आफत ने हमेशा ही देश के इस भूभाग को डराया है। इस बार की बरसात ने अपनी त्रासदी के भयंकर खंजर हमें दिए हैं, लेकिन दिल्ली से न कोई माकूल चिट्ठी और न ही संदेश आया।

अब भी हमारी दरख्वास्तें, लोगों की चीखें, खेत-बागीचों की बर्बादी का आलम, टूटते पुलों और गायब होती सडक़ की कहानियां केंद्र को अपनी व्यथा सुना रही हैं, लेकिन व्यथा का यह परिदृश्य वहां दिखाई नहीं दिया। लापचा को सरहद पर देखना देशहित का कार्य है, तो लापचा को हिमाचल में देखना भी तो जरूरी है। लापचा में हिमाचल की भी नब्ज टटोली जा सकती थी क्योंकि सीमा की रक्षा में हर दिशा में हिमाचली रक्त भी बहता है। दुश्मन की हर सरहद पर शहादतों का आंकड़ा हिमाचल के हिस्से से लगभग तीस प्रतिशत जोड़ता है, तो इस बहादुरी का अर्थ प्रदेश से मुलाकात करा सकता है। कभी यही किस्से प्रधानमंत्री हिमाचल आकर सुनाते थे। तब सिड्डू भी गर्व महसूस करता था और कांगड़ा की चाय भी रंग जमाती थी। तब हिमाचली संदर्भों की उड़ान वाकई आसमान पर थी, तो क्या अब प्रदेश ने कोई गलती कर दी। क्या जिस जनता के कसीदे तब प्रधानमंत्री कभी मंडी या कभी शिमला में पढ़ा करते थे, वह अब दोषी हो गई। प्रदेश भाजपा की सत्ता से फिसल कर कांग्रेस को क्या मिला, दोषी जनता और जनता के सरोकार हो गए। वे तमाम नदियां दोषी हो गईं जो हिमाचली दर्द को बटोर कर देश के बड़े बांधों के जरिए मैदानी इलाकों को सींचती या बिजली पैदा करके भविष्य को निरंतरता के साथ रोशन करती रही हैं। क्या वे सारी धामें, खाद्य व्यंजन, उपज, तरक्की और राष्ट्र के प्रति हिमाचल का समर्पण भी दोषी हो गया। क्या प्रधानमंत्री के इंतजार में बिछाई गई पादुकाएं सियासी हो गईं या प्राकृतिक आपदा में हिमाचल के आंसू अब बेमतलब हो गए। याद करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव से पूर्व दर्जन भर दौरे, संबोधन और आश्वासन जो हमारे हर सूर्योदय में शरीक होते थे, लेकिन अब लगता है कि सियासी ग्रहण से ओतप्रोत भावनाएं, भाव भंगिमाएं दिखा रही हैं। क्या कमाल है देश का संघीय ढांचा और लोकतंत्र का लबादा कि हर हिसाब-किताब, दर्द और इम्तिहान भी चुनावी या सियासी हो गया। क्या सुक्खू सरकार अवैध है कि प्रधानमंत्री अपने रिश्तों की फेहरिस्त भूल गए या हमारा दर्द फर्जी है जो मानवीय चीखें दिल्ली में हार गईं। ऐसे में हिमाचल भाजपा या भाजपा के नेताओं से क्यों न पूछा जाए कि प्रदेश के संघर्ष में उनकी भूमिका आखिर अब है कहां। कल अगर केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में भाजपा की सत्ता आ जाए, तो क्या इसी तरह प्रदेश की फरियाद तहस नहस होती रहेगी। सरकारें आती-जाती रहेंगी और नेता भी बदलते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र की शर्तों में यह फरेब सही नहीं कि योजनाएं व प्राथमिकताएं अपनी आंखों में भेदभाव का सुरमा लगा कर अन्याय करें। करीब तेरह हजार करोड़ की आपदा हानि के लिए हिमाचल को अगर भाजपा मजबूर देखना चाहती है, तो पढ़े-लिखे नागरिक समाज की भी तौहीन है।

मोबाइल कहीं अभिशाप न बन जाए

प्रो. सुरेश शर्मा

थोड़ी देर के लिए अपने आप को मोबाइल के बिना महसूस करें, मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसा लगेगा जैसे जीवन नीरस, असहज, असुरक्षित और शक्तिहीन हो गया है। आज संचार तकनीक का यह बच्चा यानी मोबाइल अब जवान हो गया है। दुनिया भर के ज्ञान-विज्ञान, तकनीक, सूचना, मनोरंजन की इस प्रतिमूर्ति ने दुनिया को मुठ्ठी में कर रखा है। यह उपकरण अब हर व्यक्ति की जेब में अपनी जगह बना चुका है। हर रोज घर से निकलते हुए हम माता-पिता, पत्नी, बच्चों को अभिवादन करना भूल जाएं, अपने इष्ट देव के समक्ष नतमस्तक न हों, परन्तु अपना मोबाइल तथा चार्जर लेना नहीं भूलते। कितने बेबस हो गए हैं हम? एयरटेल का व्यावसायिक एड 'कर लो दुनिया मु_ी में' कितना आकर्षक लगता था? लेकिन दुनिया को मुठ्ठी में कर लेने वाला व्यक्ति अब स्वयं ही मोबाइल की मु_ी में हो चुका है। सच में मोबाइल ने आज व्यक्ति को अपने बाहुपाश में लेकर अपना गुलाम बना दिया है।

आज बच्चे से लेकर हर बूढ़ा व्यक्ति मोबाइल के नशे में हो चुका है। मजदूर, दिहाड़ीदार, रेहड़ी-फड़ी, छोटा-मोटा काम-धंधा करने वाला व्यक्ति भी मोबाइल पर पूर्ण रूप से आश्रित है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मोबाइल आज के मनुष्य को अपना दास बना चुका है। मोबाइल का नशा अनेकों प्रकार के नशीले पदार्थों से भयंकर हो चुका है। आने वाले समय में शराब, धूम्रपान या अन्य नशीले पदार्थों को छुड़ाने के 'डी एडिक्शन सेंटर्स' की तरह एक सप्ताह या एक महीने में मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक, सलाहकार या परामर्शदाता केन्द्र खुलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। हम स्वीकार करें य न करें, लेकिन सत्य यही है कि हम सभी इस मोबाइलेरिया से मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हैं। संचार, तकनीक तथा मोबाइल क्रान्ति ने हमारा जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। इस तकनीक ने 'गूगल देवता' के माध्यम से दुनिया भर का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रेषित एवं प्रस्तुत कर दिया है। यह ठीक है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, सूचना क्रांति के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती।

शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य, संचार, तकनीक, विज्ञान, परिवहन, व्यवसाय, पुलिस, फौज, सुरक्षा, रेल, विमान, स्टॉक एवं शेयर मार्केट तथा बैंक में संचार संसाधनों का प्रयोग हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की व्यवस्थाओं का प्रबंधन इंटरनेट तथा मोबाइल कनैक्टिविटी से हो रहा है। मोबाइल ने व्यावसायिक फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, केलकुलेटर, रेडियो, टेपरिकॉर्डर, टाइपिंग आदि के व्यवसाय भी लगभग बंद ही करवा दिए हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वाट्सऐप, मैसेंजर आदि एप्स का बोलबाला है। टेलीफोन भी लगभग समाप्त ही है। मोबाइल ने फिल्म उद्योग को भी बहुत प्रभावित किया है। एमाजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट आदि ने दुकानदारी तथा व्यवसाय को बहुत प्रभावित किया है। बैंक का लेनदेन, रेल, विमान तथा परिवहन, फिल्म टिकट तथा बुकिंग मोबाइल से होती है। अब पैसे के लेनदेन, बिजली-पानी के बिल भुगतान के लिए काउंटर पर नहीं जाना पड़ता। शिक्षा क्षेत्र में मोबाइल का प्रयोग हो रहा है। वैश्विक कोरोना महामारी के समय तो मोबाइल और भी सशक्त हो गया। अब तो युवा माताएं अपने बच्चों को खुश रखने के लिए कार्टून लगाकर मोबाइल देती हैं ताकि उनका लाड़ला मोबाइल पर मस्त रहे तथा परेशान न करे। यह सब होने के बावजूद वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति इस सुविधा का प्रयोग करते हुए बहुत परेशान है। सुबह उठते ही हाथ मोबाइल पर जाता है। सुप्रभात का सन्देश भेजना, किसी भी त्योहार, दिवस, जन्म दिन शुभ कामनाएं, शोक संदेश, नवीन समाचार, सांत्वना, दुनिया भर की सूचनाएं देखने तथा आदान-प्रदान करने से लेकर संगीत, फोन काल्स, मैसेज, चैटिंग क्या नहीं होता? शाम को सोने से पहले इस लाडले मोबाइल के साथ हम अपना कुछ समय अवश्य गुजारते हैं। माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, सगे सम्बन्धियों,

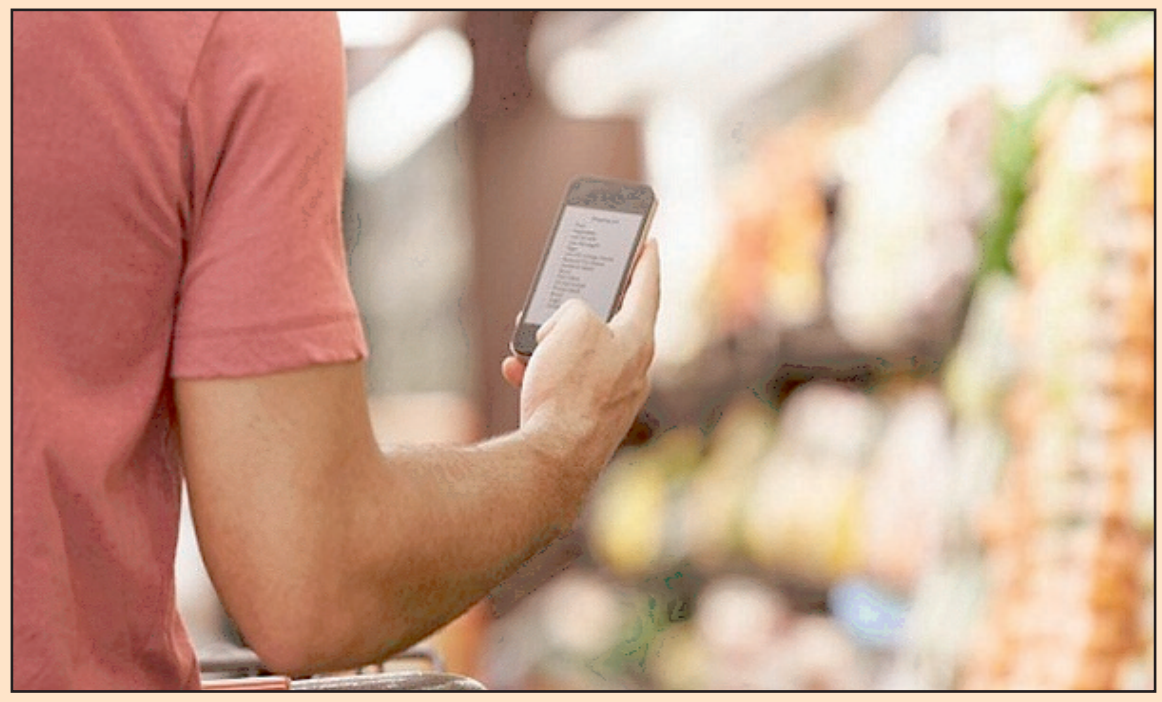

दोस्तों, कार्यालय सहयोगियों के साथ बैठे हुए भी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सम्बन्ध न निभाते हम मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं।

पढऩे वाला बच्चा, माता-पिता, अध्यापक, कर्मचारी सभी अपने को सन्तुष्ट करने के लिए 'यूज ऑफ टेक्नोलॉजी' का बहाना लेते हैं। पूरी दुनिया इस टैक्नोलॉजी में व्यस्त और मस्त हो चुकी है। सूचनाओं की इस दुनिया में वास्तविक ज्ञान तथा अध्ययन के लिए किसी के पास समय नहीं है। पाठशालाओं, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में लगभग शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के पास मोबाइल है। महाविद्यालयों में तो एक समय में लगभग सत्तर प्रतिशत विद्यार्थियों को मोबाइल पर देखा जा सकता है। विद्यार्थियों की सारी रचनात्मक गतिविधियों, लेखन, पुस्तकालय अध्ययन, खेलकूद, गीत-संगीत, समाज सेवा को ग्रहण लग चुका है। बहुत कम विद्यार्थियों में सकारात्मकता, रचनात्मकता तथा कुछ नवीन करने का जज्बा बचा है। कुछ ही बच्चे कुछ व्यावहारिक तथा सकारात्मक कार्य करने के लिए आत्म प्रेरित हैं। बच्चों की मानसिक, भावनात्मक तथा संवेगात्मक तथा संवेदनशीलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। गरीब से गरीब परिवार से सम्बन्धित बच्चा भी अपने माता-पिता पर अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने का दबाव बनाता है। अभिभावक परेशान हैं। मोबाइल न देने, कम प्रयोग करने के कारण अनेकों पढऩे वाले बच्चे आत्महत्या तक कर चुके हैं।

धड़ाधड़ रिचार्ज करवाया जाता है। सच्ची-झूठी सूचनाओं का इतना प्रवाह हो चुका है कि व्यक्तियों को अनेकों मानसिक बीमारियां, आंखों में जलन, चिड़चिड़ापन, क्रोध, मानसिक थकान, असंतोष तथा अशांति घेरने लगी है। प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैचारिक प्रदूषण पनप रहा है। मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को अकेले में ही रोते तथा हंसते हुए देखा गया है। एक अध्ययन के अनुसार मोबाइल से दस प्रतिशत बच्चों की आंखें टेढ़ी तथा अ_ारह प्रतिशत बच्चों की आंखों की दृष्टि कमजोर हो चुकी है। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में जाने वाले विद्यार्थी मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। अब इससे छुटकारा पाने के लिए डाक्टरों तथा मनोवैज्ञानिकों की कंसल्टेशन भी ली जा रही है। मोबाइल का किस तरह सकारात्मक, रचनात्मक तथा कम प्रयोग करें, इसके लिए शिक्षण संस्थानों में विशेष व्याख्यान आयोजित करवाए जा रहे हैं। सामान्य नागरिक, माता-पिता, अध्यापक-बुजुर्ग, मोबाइल के बढ़ते प्रयोग से प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। मोबाइल क्रान्ति हमारे लिए वरदान है, लेकिन इसका अत्यधिक प्रयोग कहीं हमारे लिए अभिशाप न बन जाए, इसका ध्यान रखना होगा।

काजी, पाजी को जंगल की सलाह

मैं अपने मुहल्ले का काजी हूं। काजी का पद यों ही नहीं ओन किया जा सकता जनाब! इस पद को पाने के लिए मुहल्ले में बीसियों के शांत घरों में लड़ाई झगड़े करवाने पड़ते हैं। प्रेम से रह रहे पत्नी पति के बीच शक की दीवार खड़ी करवानी पड़ती है। भाई को भाई का न चाहते हुए भी दुश्मन बनवाना पड़ता है। इसलिए जिस मुहल्ले को अपने मुहल्ले में कलह कलेश जगाने हों, वे अपने मुहल्ले में काजी का पद क्रिएट करें। जिस मुहल्ले में काजी नहीं होता, उस मुहल्ले में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। प्रेम भाव से शांत रहने वाला मुहल्ला श्मशान की तरह नहीं, कब्रिस्तान की तरह होता है। काजी ही शांत मुहल्ले को गतिशील बनाता है। वह पहले मुहल्ले में भाईचारे की छाती पर मूंग दलता लड़ाई झगड़े करवाता है और फिर लडने वालों को अपने चरणों में बिठाता है। दोनों में से एक को इंसाफ देने की कसम खाता दोनों से खाता है और बाद में उसके पक्ष में इंसाफ का निष्पक्ष फैसला सुनाता है जिसने उसके मुंह में दूसरे से अधिक पाया हो। कल मुझ कन्वेंशनल काजी के पास अजीब सा मुहल्ले का केस आया। वे अपनी बीवी से अपनी बीवी की कस्टडी के बदले ज्वाइंट कुत्ते की कस्टडी चाह रहे थे। उनका दावा था कि कुत्ता उनका है। क्योंकि वे भी बहुत कुछ कुत्ते से ही हैं। इसलिए न्याय यही कहता है वह उनकी कस्टडी में रहना चाहिए। दूसरी ओर उनकी बीवी का तर्क था कि उन्हें अपने पति से कोई लेना देना नहीं। वह कुत्ते से भी लोअर क्लास है। वह उसे अपनी कस्टडी में अब और नहीं रख सकती। इसलिए कुत्ता उनकी कस्टडी में ही रहेगा।

इसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं। क्योंकि वह कम से कम उनसे डरता तो है। बीवियों को वही कस्टडियां पसंद होती हैं जो कम से कम उनसे डरती रहें। ऐसों को पालने में ही उनका पति धर्म सुरक्षित रहता है। मामला सचमुच पेचीदा था। और मैं ठहरा छोटे मुहल्ला लेबल का काजी। समझ नहीं आ रहा था दोनों को चबाने के बाद फैसला किसके पक्ष में दूं। क्योंकि दोनों ही अपने अपने पक्ष में न्याय दिलवाने को बराबर बराबर खिला रहे थे। थक हार कर मैं पाजी काजी उनके फैमिली मैटर में टांग फंसाता चिंतन करता जंगल की ओर निकल पड़ा। काजी की निष्पक्ष मुफ्त की राय! जंगल के मामले जब भरे पूरे सभ्य शहर में होने लगें तो तुरंत चिंतन करने जंगल की ओर निकल जाइए, समाधान मिल जाएगा। अभी जंगल की ओर दो ही कदम धरे थे कि सामने जंगल खड़ा मिला। जंगल होने के लिए अब पेड़ों की जरूरत नहीं। जंगल होने के लिए अब डर की जरूरत नहीं। जंगल होने के लिए अब सन्नाटों की जरूरत नहीं। वे तो जंगल से भी गहरे अब शहरों में होने लगे हैं। 'क्या सोच रहे हो काजी साहब? न्याय करने के लिए सोचने कब से लग गए?' जंगल ने मुझसे पूछा तो मैंने निष्पक्ष काजी होते कहा, 'हे जंगल! पहली बार न्याय करना चाहता हूं।

सलाह दे! कुत्ता उनकी पत्नी की कस्टडी में रहे या उनके पति की कस्टडी में?' पुरुष प्रधान समाज में बिन सोचे उनके पति की कस्टडी में दे दो काजी साहब! अब न्याय के लिए जंगल से क्या राय? मेरे तो तुमने सूअर तक कानूनन छीन अपनी कस्टडी में ले लिए। मेरे तो सियार तक मुझसे कानूनन छीन तुमने अपनी कस्टडी में लिए। मेरे तो गिरगिट तक तुमने कानूनन मुझसे छीन अपनी कस्टडी में ले लिए। मेरे तो भेड़िए तक कानूनन मुझसे छीन तुमने अपनी कस्टडी में ले लिए। अरे काजी साहब! मेरे तो सांप भी तुमने मुझसे छीन कानूनन छाती चौड़ी कर अपनी कस्टडी में ले लिए। पर काजी साहब! उनसे कहो कि अब उन्हें कुछ कस्टडी में लेना ही है तो सच की कस्टडी में लो। उनसे कहो कि उन्हें कुछ कस्टडी में लेना ही है तो ईमानदारी की कस्टडी लो। उनसे कहो कि उन्हें कुछ कस्टडी में लेना ही है तो प्रेम की कस्टडी लो। उनसे कहो कि उन्हें कुछ कस्टडी में लेना ही है तो रिश्तों की गर्माहट की कस्टडी लो।

अक्टूबर में 6.21 प्रतिशत बढ़कर 33.57 अरब डालर रहा वस्तु निर्यात, व्यापार घाटा भी बढ़ा

इस साल अक्टूबर में वस्तु निर्यात 6.21 प्रतिशत बढ़कर 33.57 अरब डॉलर तक पहुंच गया। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में आयात बढ़कर 65.03 अरब डॉलर हो गया जो पिछले साल की समान अवधि में 57.91 अरब डॉलर था। हालांकि अगर चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक वस्तुओं के निर्यात की बात करें तो ये सात फीसदी गिरकर 244.89 अरब डॉलर पर आ गया।

नई दिल्ली। इस साल अक्टूबर में वस्तुओं का निर्यात 6.21 प्रतिशत बढ़कर 33.57 अरब डॉलर रहा है। बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में आयात बढ़कर 65.03 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 57.91 अरब डॉलर था।

बढ़ा व्यापार घाटा

अक्टूबर में व्यापार घाटा बढ़कर 31.46 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में व्यापार घाटा 26.31 अरब डॉलर था।

हालांकि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान वस्तुओं के निर्यात की बात करें तो यह सात प्रतिशत घटकर 244.89 अरब डॉलर रहा। वहीं आयात इस दौरान 8.95 प्रतिशत घटकर 391.96 अरब डॉलर रहा। खास बात यह है कि फरवरी-जुलाई के दौरान देश का निर्यात नकारात्मक दायरे में था। मंत्रालय द्वारा संख्या में संशोधन के बाद अगस्त में इसमें 3.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई, लेकिन सितंबर में इसमें 2.6 प्रतिशत की गिरावट आई।

आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में 30 प्रमुख क्षेत्रों में से 22 में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। इसी तरह दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 के दस महीनों की नकारात्मक वृद्धि के बाद आयात भी बढ़ा है।

किन उत्पादों का कितना आयात?

अक्टूबर में जिनका सबसे ज्यादा आयात किया गया, उसमें दालें (112.2 प्रतिशत), फल और सब्जियां (53.4 प्रतिशत), अलौह धातु (21.24 प्रतिशत) और इलेक्ट्रानिक्स सामान (26 प्रतिशत) शामिल हैं।

इस दौरान सोने का आयात 95.5 प्रतिशत बढ़कर 7.23 अरब डॉलर हो गया। अक्टूबर में तेल का आयात भी आठ प्रतिशत बढ़कर 17.66 अरब डॉलर रहा।

इनके निर्यात में हुई वृद्धि

लौह अयस्क, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, फार्मा, इलेक्ट्रानिक सामान, कालीन, प्लास्टिक, समुद्री और इंजीनियरिंग के सामानों के निर्यात में हुई वृद्धि। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा,

मुझे उम्मीद है कि हम पिछले साल के आंकड़ों को पार कर जाएंगे। कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के बावजूद सकारात्मक वृद्धि हुई है। हम इंतजार कर रहे हैं और वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

व्यापार के आंकडें निर्यात क्षेत्र में पुनरोद्धार का संकेत है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरें और मुद्रास्फीति अभी भी ऊंची हैं। हम निर्यात के अवसर तलाशने के लिए नए बाजारों पर विचार कर रहे हैं।

28.7 अरब डॉलर रह सकता है सेवा निर्यात

अक्टूबर में सेवाओं का निर्यात 28.7 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। पिछले साल की समान अवधि में यह 25.3 अरब डॉलर था। वहीं सेवाओं का आयात 13.51 अरब डॉलर के मुकाबले 14.32 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। अप्रैल से अक्टूबर, 2023 के दौरान निर्यात की गई सेवाओं का अनुमानित मूल्य 192.65 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। पिछले साल की समान अवधि में यह 181.37 अरब डॉलर रहा था।

RBI ने लिया बजाज फाइनेंस पर बड़ा एक्शन, eCOM और Insta EMI Card से लोन की मंजूरी पर लगाई रोक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज बजाज फाइनेंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो ऋण उत्पादों 'eCOM' और 'Insta EMI Card' के तहत ऋण की मंजूरी और वितरण तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक ने तय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। कंद्रीय बैंक ने कहा कि इस पाबंदी की समीक्षा उक्त कमियों को दूर करने के बाद होगी।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज बजाज फाइनेंस पर बड़ी कार्यवाई की है। कंद्रीय बैंक ने बजाज फाइनेंस को दो ऋण उत्पादों 'eCOM' और 'Insta EMI Card' के तहत लोन की मंजूरी और वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है।

आरबीआई ने क्यों लिया एक्शन?

आरबीआई के मुताबिक बजाज फाइनेंस ने डिजिटल लोन के लिए तय दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है, खासकर 'eCOM' और 'Insta EMI Card' लोन उत्पादों के तहत उधारकर्ताओं को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करने और मुख्य तथ्य में कमियों के कारण यह एक्शन लिया गया है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा कि इस फैसले की समीक्षा उक्त कमियों को दूर करने के बाद होगी।

आरबीआई ने पिछले साल जारी किया था दिशानिर्देश

पिछले साल अगस्त में, रिजर्व बैंक ने लेनदार के हितों की रक्षा के उद्देश्य से डिजिटल लोन पर दिशानिर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के मुताबिक विभिन्न अनुमेय क्रेडिट सुविधा सेवाओं का विस्तार करने के लिए आरबीआई विनियमित संस्थाओं (आरई) और उनके द्वारा संलग्न लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर (एलएसपी) के डिजिटल लोन पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है। इससे पहले जनवरी 2021 में, केंद्रीय बैंक ने 'डिजिटल ऋण' पर एक कार्य समूह का गठन किया था, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन देना शामिल था। बजाज फाइनेंस ने हाल ही में सितंबर तिमाही के नतीजों को जारी करते हुए बताया था कि उसका कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 28 प्रतिशत बढ़कर 3,551 करोड़ रुपये हो गया था।

इनसाइड

दीवाली के बाद महंगा हुआ सोना-चांदी, जानिए आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

देश में आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। पिछले दिनों देश में धनतेरस और दिवाली के दिन गोल्ड की डिमांड बढ़ गई थी ऐसे में इनकी कीमतों में नरमी देखने का मिली है। अगर आप गोल्ड खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको अपने शहर में सोने की कीमतों के बारे में जान लीजिए।

नई दिल्ली। दिवाली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि, दिवाली और धनतेरस के मौके पर इनकी कीमतों में नरमी देखने को मिली थी। अगर आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको एक बार अपने शहर में गोल्ड और लेटेस्ट रेट क्या है?

महंगा हुआ सोना

आज वायदा कारोबार में सोने की कीमत 310 रुपये बढ़कर 60,375 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर, दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध की कीमत 310 रुपये या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 60,375 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 9,897 लॉट का कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना वायदा 0.45 प्रतिशत बढ़कर 1,975.30 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया।

चांदी के दाम चढ़े

बुधवार को वायदा कारोबार में चांदी की कीमत 598 रुपये बढ़कर 72,191 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, क्योंकि मजबूत हाजिर मांग के कारण प्रतिभागियों ने अपने सौदे बढ़ा दिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 598 रुपये या 0.84 प्रतिशत बढ़कर 18,241 लॉट में 72,191 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।

वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 1.01 प्रतिशत बढ़कर 23.37 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

आपके शहर में क्या है सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,190 रुपये है।

नोएडा में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,190 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपये है।

चैन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,580 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपये है।

केरल में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,040 रुपये है।

पटना में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,090 रुपये है।

सूरत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,090 रुपये है।

चंडीगढ़ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,090 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,090 रुपये है।

इंडिया-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को इजरायल-हमास संघर्ष से खतरा: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो भारत को मध्य पूर्व में यूरोपीय देशों से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे पूरे क्षेत्र के देशों को लाभ होगा उसे इजराइल और गाजा पट्टी में चल रहे तनाव के कारण खतरा हो सकता है। जानिए इस कॉरिडोर में क्या-क्या होंगी सुविधाएं।

नई दिल्ली। भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोपीय देशों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना इंडिया मिडिल-ईस्ट कॉरिडोर (IMEC) से इस समूचे क्षेत्र के देशों को फायदा होगा लेकिन इजरायल व गाजा में चल रहा तनाव से इसको खतरा भी है।

शिपिंग बीमा कंपनी का गठन

यह बात भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां हिंद प्रशांत क्षेत्रीय परिचर्चा में अपने विशेष अभिभाषण में कही। इसी मंच से उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वैश्विक मंच पर जहाजरानी उद्योग की बढ़ती अहमियत और देश के व्यापक रणनीतिक हितों को देखते हुए भारत अपनी शिपिंग बीमा कंपनी का गठन करेगा।

भारतीय ही होंगे इस कंपनी के प्रोमोटर

यह कंपनी पूरी तरह से भारतीय होगी यानी इसके प्रवर्तक भारतीय होंगे व यह भारत से ही संचालित होगी। इस पर किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने भारतीय इकोनमी की मजबूती के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनमी बनने को तैयार है।

भारत की विकास दर 7 फीसदी से रहेगी नीचे

चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर सात फीसद से नीचे रहने वाली है। लेकिन यह प्रमुख देशों में आर्थिक विकास की सबसे तेज गति होगी। विपरीत वैश्विक हालातों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था एक सही राह पर है और एक सुखद भविष्य की तरफ बढ़ रही है। हाल के सप्लाई चेन आपूर्ति की बाधाओं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में विवाद होने, यूक्रेन से लेकर इजरायल-गाजा में तनाव होने के बावजूद भारतीय इकोनमी पूरी दुनिया में एक चमकता सितारा बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। तब भारत की इकोनमी का आकार पांच अरब डॉलर का होगा और यह जर्मनी व जापान से आगे निकल जाएगा। वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बनने की इच्छा रखता है

शिपिंग संचालन को अधिक सुरक्षित बनाने का प्लान

वित्त मंत्री ने कहा कि हम शिपिंग को लेकर होने वाले कानूनी प्रक्रियाओं में अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के खतरे को कम करने के लिए और अपने शिपिंग संचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से भारतीय हिस्सेदारी व भारत केंद्रित प्रोटेक्शन व इंडेमनिटी (पीएंडआई) निकाय स्थापित कर रहे हैं।

यह सभी तरह के शिपिंग कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके पहले उन्होंने बताया कि भारत की समग्र राष्ट्रीय शक्ति इसकी समुद्री शक्ति से जुड़ी हुई होगी। भारत सरकार समुद्री सेक्टर को बढ़ाने व इसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए हर तरह का नीतिगत मदद करने को प्रतिबद्ध है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम भारत को नई सप्लाई चेन के केंद्र के तौर पर स्थापित करना चाहते है। इस उद्देश्ये से सरकार के सारे विभाग आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं।

IMEC कॉरिडोर में सुविधाएं

IMEC कॉरिडोर के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि यह शिपिंग, रेलवे और रोड नेटवर्क के साथ ही बिजली के तार, हाई-स्पीड डाटा और हाइड्रोजन पाइपलाइन से सुसज्जित होगा। यह भारत के जेएनपीए, मुंद्रा और कांडला पोर्ट को पश्चिमी एशिया के फुजैरैया, जाबेल अली, अबुधाबी, दम्माम, रास अल खैर और घुवैफत बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगा।

इसके बाद ये कारीडोर सउदी अरब के हराध व अल-हदिथा पोर्ट व इजरायल के हाइफा से भी जोड़ा जाएगा। यह दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप व मध्य पूर्व के बीच आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाएगा। पूरे क्षेत्र में कारोबार करने की लागत घटेगी। यह सभी देशों के लिए फायदे का होगा। लेकिन भूराजनीतिक चुनौतियां भी होंगी। इजरायल और गाजा का मौजूदा विवाद के इसके लिए चिंताजनक परिणाम हो सकते हैं।

वित्त वर्ष 24 के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टारगेट को पार जाएगी सरकार: सीबीडीटी चेयरमैन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि इस बार सरकार वित्त वर्ष 2024 के लिए निर्धारित 18.23 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य को पार कर जाएगी। हाल ही में जारी शुद्ध प्रत्यक्ष कर राजस्व के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 9 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर राजस्व 22 प्रतिशत बढ़कर 10.6 लाख करोड़ रुपये हो गया।

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि वित्त वर्ष 24 के लिए निर्धारित 18.23 लाख करोड़ रुपये के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के टारगेट को इस बार सरकार पार कर जाएगी।

मीडिया से बात करते हुए नितिन गुप्ता ने बताया

हम बजट लक्ष्य को पार कर जायेंगे। अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और 15 दिसंबर तक अग्रिम कर संख्या की तीसरी किस्त आने के बाद हमें पूरे साल के कर संग्रह की बेहतर तस्वीर मिलेगी।

कितना रहा था नेट डायरेक्ट कलेक्शन?

हाल ही जारी हुए नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मुताबिक इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 9 नवंबर के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22 प्रतिशत बढ़कर 10.60 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

नितिन गुप्ता ने बताया सकल आधार पर, प्रत्यक्ष कर संग्रह 17-18 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि शुद्ध आधार पर, हम 22 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे हैं। हम साथ-साथ रिफंड भी जारी कर रहे हैं। इसलिए, हमें अनुमान से अधिक कर संग्रह होने में कोई संदेह नहीं है

कितने करोड़ का रिफंड हुआ जारी?

आंकड़ो के मुताबिक 1 अप्रैल से 9 नवंबर के बीच कुल 1.77 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं। 2023-24 के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.23 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 16.61 लाख करोड़ रुपये से 9.75 प्रतिशत अधिक है।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बचे हैं बस 15 दिन, घर बैठे पोस्ट के जरिए ऐसे करें सबमिट

परिवहन विशेष न्यूज

जीवन प्रमाण पत्र नवंबर महीने में सभी पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए केवल 15 दिन बचे हैं। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आप पोस्ट के जरिये भी आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं।

नई दिल्ली। जिन भी व्यक्ति को सरकार द्वारा पेंशन का लाभ मिलता उन सभी पेंशनर्स को नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Pramaan Patra) जमा करवाना होता है। वह यह सर्टिफिकेट बैंक या फिर ऑनलाइन जाकर जमा कर सकते हैं। वहीं जो वृद्ध पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक नहीं जा सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन पेंशन सबमिट करने का प्रोसेस नहीं पता है वो आसानी से पोस्ट ऑफिस की मदद से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस से कैसे जमा होता है जीवन प्रमाण पत्र

अगर आप पोस्ट ऑफिस से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहते हैं तो आपको डाकिये को अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट और बायोमेट्रिक डिटेल्स देनी होगी। इसके साथ उन्हें 70 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क देना होगा। पेंशनर्स अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए उन्हें फिजिकल रूप से बैंक या फिर किसी और कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। वह डीएलसी जनरेट करने के लिए आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) पेंशनर्स को डोरस्टेप की सुविधा देते हैं। इसका मतलब है कि पेंशनर्स घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है ये डॉक्यूमेंट

पेंशनर्स के पास आधार नंबर होना अनिवार्य है।

उनके पास पेंशन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए।

पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी के पास आधार नंबर का पंजीकरण होना चाहिए।

पेंशनर्स को उनके पेंशन के प्रकार और सेक्शनिंग अथॉरिटी डिसबर्सिंग एजेंसी, पीपीओ नंबर और अकाउंट नंबर की (पेंशन) के बारे में पता होना चाहिए।

सडक हादसों में बहते खून और मौतों का दोषी कौन?

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। देशभर में सडकों का जाल तो बिछाया जा रहा है। बडे और चौडे हाई-वे,के निर्माण के अलावा लम्बी -उंची एलिवेटिड सडकों का भी निर्माण बडे स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में सडक हादसों पर जारी सरकारी रिपोर्ट ने वाहन चालकों का खून और सुखा दिया है।पेश रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल यानि 2022 में 4.61 लाख सडक हादसे हुए। इन दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों की मौत ने सडकों का रंग खून से लथपथ कर दिया । इन हादसों का आखिर दोषी कौन है? इस पर सत्ता आखिर मौन क्यों है। हादसों में सडकों पर बहे खून की वास्तविक भयावह बहुत ही बडा आंकडा है। इन आंकडों के एनालिसिस करने पर पता चलता है कि तकरीबन हर घंटे में 53 रोड एक्सीडेंट हुए। सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये सूरतेहालात मंत्रालय के लिए आईना ही काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हुए कुल सडक हादसों में 32.9 फीसदी हादसे एक्सप्रेसवे एंव राष्ट्रीय राजमार्गो पर हुए। वहीं 106682 यानि 23.1फीसदी % हादसे राज्य मार्गो, जबकि 43.9 प्रतिशत रोड एक्सीडेंट अन्य सडकों में गिनाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सडक दुर्घटनाओं में बढोतरी 11.9 प्रतिशत की हुई। और उनमें मौत के आंकडे में भी 9.4 % की बढोतरी दर्ज हुई। वही हादसों में घायलों की संख्या में भी 15.3 % की बढोतरी दर्ज की गई है।रिपोर्ट के मुताबिक सीट बैल्ट ना लगाने की वजह से 16,715 लोगों की मौत हुई। इन मौंतो में 8384 लोग ड्राइवर थे। और 8331 लोग सफर करने वाले थे। इसके अलावा मौत के शिकार बने 50,029 लोग दो पहिया सवार थे। जिन्होने हेल्मेट नहीं पहना हुआ था। अब सवाल उठता है कि मौत के आंकडों और बडती सडक दुर्घटनाओं में साल दर-साल होती बढोतरी के कारणों को ढूंढने की बजाए देशभर में सडक विस्तार पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है। पर सडकों को खून से लथपथ होने से रोकने पर तवज्जो खास नही है। सरकार को चाहिए कि सडक विस्तार के साथ-साथ ही लोगों की कीमती जानों को बचाने पर भी को तेजी से काम करना चाहिए। इसके अलावा कमर्शियल निजी

ड्राइवरों के काम करने के घंटों में भी कानून बनाकर 8-10 घंटे का तय होना चाहिये। जो फिलहाल 14-15 घंटों की ड्राइवरी सबसे बडी एक्सीडेंट की वजह है। दूसरे ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन के साथ ड्राइवर की उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्पीड लिमिट , के अलावा शराब पीकर गाडी चलाने का हमेशा के लिए लाईसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए।गाडी का उचित रखरखाव,मेंटेनेंस का भी डाटा जरूरी तौर पर तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा कमेटी का गठन कर रोड एक्सीडेंट के कारण और निदान पर कार्यो को अंजाम देना भी जरूरी है। खालिस रोड विस्तार और सालाना हादसों के आंकडों को पेश करने के अलावा , रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों और सुधार पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए।

नरसिंह मिश्रा ने पश्चिम ओडिशा की उपेक्षा की बात कही. उन्होंने कहा, जरूरी हुआ तो विशेष सशक्त राज्य की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहेगा.

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबनेस्वर : कांग्रेस विधायक नरसिंह मिश्रा ने कलाकार के मुंह में कोशल राज्य दोहराया. नरसिंह ने कहा कि अलग राज्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी. कांग्रेस विधायक ने बलांगीर के लोइसिंघा स्टेडियम में एक फुटबॉल मैच के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही.नरसिंह ने कहा कि राज्य सरकार पश्चिम ओडिशा की उपेक्षा कर रही है, पैसा स्वीकृत होने के बावजूद जारी नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिनेमा, कला, रोजगार, रोज़गार आदि क्षेत्रों में पश्चिम ओडिशा की उपेक्षा की जा रही है. अगर सरकार पश्चिम ओडिशा का विकास नहीं करेगी तो राज्य दो राज्यों में बंट जायेगा. इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. नरसिंह ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए कहा, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब रायपुर में हाईकोर्ट की स्थायी श्रृंखला की स्थापना की मांग की गई थी. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी अनदेखी कर छत्तीसगढ़ का विभाजन कर दिया गया। नरसिंह ने कहा कि अगर पश्चिम ओडिशा की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो ओडिशा विभाजित हो जाएगा।

'केजरीवाल सरकार नहीं चाहती लोग यमुना किनारे छठ मनाए' , बीजेपी ने कहा- हिंदुओं की आस्था से हो रहा खिलवाड़

- सचदेवा का आरोप- AAP सरकार ने कहा कि छठ पूजा से होता है यमुना में प्रदूषण
- मनोज तिवारी ने कहा- नदी में जहरीला रसायन और नाले का पानी डाला जा रहा

दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर यमुना किनारे छठ पूजा नहीं होने देने को लेकर आरोप लगाए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप सरकार कोर्ट में शपथ पत्र देकर यह तर्क दे रही है कि छठ मनाए जाने से यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है। आप सरकार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रही है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर अदालत से यमुना में छठ पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध लगवाने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है।

दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 1993 में मदन लाल खुराना के मुख्यमंत्री बनने पर यमुना किनारे छठ पूजा के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। यमुना की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाली यह सरकार इस परंपरा को रोक रही है।

उन्होंने कहा कि यह सरकार अदालत में जाकर शपथपत्र देती है कि छठ पूजा करने से यमुना में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। वायु एवं जल प्रदूषण रोकने में नाकाम यह सरकार हिंदू त्योहारों को बदनाम कर रही है। किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दिल्ली में व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग छठ पूजा करने के लिए अपने गांव जा रहे हैं।

विदेशों में हो रही है छठ पूजा: तिवारी

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पूरे देश के साथ अमेरिका और अन्य देशों में नदी एवं जल स्त्रोत के किनारे छठ पूजा का आयोजन होता है, लेकिन दिल्ली सरकार यमुना किनारे छठ के आयोजन पर प्रतिबंध लगा रही है। यमुना में जहरीला रसायन और नाले का पानी डाला जा रहा है। वहीं, गंगा जल और गाय का दूध डालने से रोका जा रहा है। हिंदू संस्कृति पर यह सरकार चोट पहुंचा रही है। वर्ष 2025 में भाजपा की सरकार आएगी और दिल्ली के लोग यमुना किनारे छठ मनाएंगे।

'केजरीवाल की फोटो लगाने की शर्त'

प्रदेश भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक हजार छठ घाट बनाने की घोषणा की थी, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। आईटीओ छोड़कर अन्य स्थानों पर छठ घाट की अब तक साफ सफाई भी नहीं हुई है। कई स्थानों पर अभी गड्ढे बनाए जा रहे हैं। छठ समितियों के सामने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाने पर ही फंड देने की शर्त रख रहे हैं। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह व अन्य नेता उपस्थित थे।

भारत 12 साल बाद फाइनल में, न्यूजीलैंड से लिया 2019 की हार का बदला; कोहली-अय्यर के बाद छाए शमी

भारत की जीत में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी का योगदान अहम रहा। कोहली ने 117 और अय्यर ने 105 रन की पारी खेली। वहीं, मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए सात विकेट अपने नाम किए। तीनों ने मिलकर भारत को लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में नहीं हारने दिया।

नई दिल्ली। भारत ने विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। उसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार (15 नवंबर) को रोमांचक मैच में न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला भी ले लिया। भारतीय टीम 12 साल बाद टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। पिछली बार 2011 में टीम इंडिया ने घरेलू मैदान पर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी टीम चैंपियन बनी थी। भारतीय टीम अब 19 नवंबर को होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी।

भारत चौथी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वेस्टइंडीज को हराकर पहली बार खिताब जीता था। 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। तब सौरव गांगुली कप्तान थे। इसके आठ साल बाद 2011 में जब भारत फाइनल में पहुंचा तो उसने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार खिताब जीत लिया।

कोहली-अय्यर और शमी ने दिलाई जीत

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में चार विकेट खोकर 397 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में 327 पर सिमट गई। भारत की जीत में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी का योगदान अहम रहा। कोहली ने 117 और अय्यर ने 105 रन की पारी खेली। वहीं, मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी में कमाल दिखाते हुए सात विकेट अपने नाम किए। तीनों ने मिलकर भारत को लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में नहीं हारने दिया। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया अंतिम-4 के मुकाबले में हार गई थी।

रोहित-गिल ने दिलाई आक्रामक शुरुआत

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शानदार शुरुआत की। पहले रोहित ने तेज गति से रन बनाए फिर गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी की। रोहित ने विश्व कप में अपने 50 छक्के पूरे किए और टीम का स्कोर पावरप्ले के अंदर 50 रन के पार पहुंच गया। रोहित शर्मा साउदी की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में 47 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। हालांकि, पावरप्ले में टीम इंडिया एक विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाने में सफल रही। गिल और कोहली ने भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया। इस दौरान गिल ने 41 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। 65 गेंद में 79 रन बनाने के बाद गिल वानखेड़े की गर्मी से परेशान हो गए। उन्हें क्रैम्प आ रहे थे और वह मैदान के बाहर चले गए।

कोहली और अय्यर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया

विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारत का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। उन्होंने 59 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान वह एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने सचिन के 673 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। विराट और श्रेयस ने शतकीय साझेदारी कर भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंचा दिया।

विराट ने वनडे में अपना 50वां शतक लगाया और भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया। वह 117 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर भारत का स्कोर 350 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद श्रेयस ने 67 गेंद में अपना शतक पूरा किया और 70 गेंद में चार चौके और आठ छक्कों की मदद से 105 रन बनाकर आउट हुए। 49वें ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए सूर्यकुमार एक रन बनाकर आउट हो गए। अंत में लोकेश राहुल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी खत्म की। राहुल ने आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारत का स्कोर 397 रन तक पहुंचा दिया। वह 39 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, शुभमन गिल 80 रन के स्कोर पर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने तीन और ट्रेंट बोल्ट ने एक विकेट लिया।

मिचेल नहीं दिला पाए न्यूजीलैंड को जीत

न्यूजीलैंड के लिए डेरिल मिचेल ने 134 रन बनाए। कप्तान केन विलियम्सन ने 69 रन की पारी खेली। ग्लेन फिलिप्स ने 41 रन का योगदान दिया। दोनों कीवी ओपनर कॉन्वे और रचिन 13 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सात विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को एक-एक विकेट मिला।

डीटीसी बस कंडक्टर को बर्खास्त करने के 32 साल पुराने मामले में हस्तक्षेप करने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

डीटीसी बस कंडक्टर को बर्खास्त करने के निर्णय में हस्तक्षेप करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल साल 1991 में 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया था। साल 2003 में श्रम न्यायालय ने कंडक्टर की सेवा बहाल करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ डीटीसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी।

नई दिल्ली। डीटीसी बस कंडक्टर की बहाली के आदेश में हस्तक्षेप करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए इनकार कर दिया कि कंडक्टर अब जीवित नहीं है। बस कंडक्टर को साल 1991 में 15 दिनों के लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

हालांकि, अदालत ने कहा कि कंडक्टर के निष्कासन की सजा असंगत, लेकिन भले ही जुर्माने की मात्रा के लिए मामले पर पुनर्विचार किया जाए, पर कंडक्टर के जीवित नहीं होने के कारण कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

यह टिप्पणी के साथ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की अपील को खारिज कर दिया। डीटीसी ने वर्ष 2003 के श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखने वाले एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी थी। उक्त आदेश में कंडक्टर को बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था। डीटीसी द्वारा उसके खिलाफ जांच शुरू करने के बाद जनवरी 1992 में मृत कर्मचारी को सेवा से हटाने की सजा दी गई थी।

कंडक्टर के बयान पर भरोसा नहीं किया गया

अदालत ने कहा कि जांच के दौरान केवल एक गवाह से पूछताछ की गई और जांच अधिकारी ने कंडक्टर के बयान पर विश्वास नहीं किया कि उसे बीमारी के कारण 15 दिनों की छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया गया था। उसकी छुट्टी का आवेदन उसके भाई के माध्यम से भेजा गया था।

जीवित नहीं रहने पर उद्देश्य पूरा नहीं होता

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि काम करने वाला अब नहीं है और भले ही सजा की मात्रा के बिंदु पर मामले को श्रम न्यायालय में वापस भेज दिया जाए, लेकिन कर्मी के जीवित नहीं रहने के कारण कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है। अदालत को सूचित किया गया कि डीटीसी ने मृत कंडक्टर की पत्नी और कानूनी उत्तराधिकारियों को सभी टर्मिनल बकाया का भुगतान कर दिया है और बहाली के फैसले को लागू किया है।

'अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि', IPS प्रशिक्षु अधिकारियों से बोले बिरला

लोकसभा स्पीकर ने पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि है। बिरला ने पुलिस की सामाजिक भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें डर के बजाय आत्मविश्वास को प्रेरित करना चाहिए।

नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कानून प्रवर्तन के ढांचे के भीतर काम करते समय पुलिस को सांस्कृतिक और पारंपरिक पहलुओं की बारीक समझ रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बिरला ने यहां आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की, जो संसदीय प्रक्रियाओं फर एक पाठ्यक्रम में भाग ले रहे थे।

लोकसभा सचिवालय के एक बयान के मुताबिक, लोकसभा स्पीकर ने पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि है। बिरला ने पुलिस की सामाजिक भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें डर के बजाय आत्मविश्वास को प्रेरित करना चाहिए। लोगों को किसी भी अवैध या गलत गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

बिरला ने कहा कि नीतियों और प्रक्रियाओं पर खुले तौर पर जानकारी साझा करके एक पारदर्शी पुलिस प्रशासन सक्रिय रूप से सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने और कानून प्रवर्तन और उन लोगों के बीच बंधन को मजबूत करने में समाज को शामिल करता है जो इसकी सेवा करते हैं। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जांच में त्वरित और गुणात्मक परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।

लोकसभा स्पीकर ने कहा कि पिछले सत्र के दौरान पेश किए गए पुलिस और आपराधिक कानूनों से संबंधित तीन नए विधेयकों के कानून बनने के बाद इससे उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से नवाचार को अपनाने का भी आग्रह किया, जिससे उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों से निपटने की उनकी क्षमता बढ़ेगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023